घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com **अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 315- गुरूवार 17- सितम्बर 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये** RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

PF पेंशन पर सरकार का बड़ा ऐलान....51 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

ईपीएफओ में वेतन सीमा बढ़ाकर 25 हजार की गई

नई दिल्ली,16 सितम्बर 2026। केन्द्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रति माह कर दिया है। सरकार के इस फैसले से 51 लाख से अधिक कर्मचारियों के ईपीएफओ के दायरे में आने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वेतन सीमा बढ़ने से 15 हजार से 25 हजार रुपये मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग को वैधानिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का लाभ मिल सकेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि वेतन सीमा को बढ़ाने का आधार यह है कि पिछली बार 15 हजार रुपये की सीमा सितंबर 2014 में निर्धारित की गई थी। इसके बाद औसत वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और जीवन-यापन की लागत भी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि आज नियमित वेतन पाने वाले कर्मचारी की औसत मासिक आय करीब 23 हजार रुपये है, जो 2014 से पहले की अवधि की तुलना में लगभग ढाई गुना बढ़ चुकी है। कई राज्यों ने अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन भी 15 हजार रुपये से अधिक कर दिया है। सरकार के अनुसार,मौजूदा व्यवस्था में 15 हजार रुपये से अधिक मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करने वाला कर्मचारी स्वतः अनिवार्य ईपीएफ व्यवस्था के दायरे में नहीं आता।

सीमा बढ़ाकर 25 हजार रुपये किए जाने से ऐसे कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ),कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) और कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना (ईडीएलआई) के तहत उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा लाभों का दायरा बढ़ेगा। ईपीएफओ की वेतन सीमा 2004 से 2014 तक एक दशक तक अपरिवर्तित रही थी। सितंबर 2014 में इसे बढ़ाकर 15 हजार रुपये किया गया था। सरकार ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में वेतन और आय में लगातार वृद्धि तथा औपचारिक रोजगार के विस्तार को देखते हुए सीमा को 25 हजार रुपये करना जरूरी हो गया था। सरकार के मुताबिक,इस फैसले से रोजगार के औपचारिकीकरण को गति मिलेगी और कर्मचारियों के लिए दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति सुरक्षा मजबूत होगी। व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवरेज से कर्मचारियों को भविष्य के लिए अधिक सुरक्षित वित्तीय आधार मिलेगा।

ईपीएफओ वेतन सीमा क्यों बढ़ाई गई?

यह वेतन सीमा बढ़ाने का निर्णय कई महत्वपूर्ण कारकों पर आधारित है। पिछले कुछ वर्षों में देश में निरंतर वेतन वृद्धि देखी गई है। लोगों की आय में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही, औपचारिक रोजगार के क्षेत्र में भी विस्तार हुआ है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, सरकार इन सभी बदलावों को दर्शाना चाहती है। इस कदम से अधिक से अधिक श्रमिकों को संगठित क्षेत्र की सुरक्षा मिल सकेगी।

कितने कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?

इस निर्णय से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी ईपीएफओ के अनिवार्य कवरेज के दायरे में आ जाएंगे। पहले जो कर्मचारी 15,000 रुपये से अधिक वेतन पाते थे,वे इस दायरे से बाहर थे। अब 25,000 रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले सभी कर्मचारी ईपीएफओ का हिस्सा बन जाएंगे। यह श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करेगा। उन्हें भविष्य निधि और पेंशन जैसे लाभ मिलेंगे।

सरकार पर वित्तीय भार कितना पड़ेगा?

इस निर्णय से सरकार पर वित्तीय भार भी बढ़ेगा। वार्षिक बजट सहायता करीब 10,250 करोड़ रुपये है। इसके मुकाबले, वार्षिक सरकारी खर्च लगभग 11,339 करोड़ रुपये अनुमानित है। यानी, सरकार को हर साल करीब 1,089 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे। अगले पांच वर्षों में अनुमानित कुल व्यय लगभग 56,696 करोड़ रुपये होगा। यह राशि श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खर्च की जाएगी।

नहीं कम होगी इन-हैंड सैलरी

15,000 रुपये से बढ़ाकर 25000 रुपये सैलरी लिमिट करने के बावजूद भी कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी पर कोई असर नहीं होगा। क्योंकि यह हिस्सा आपके एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 12 फीसदी में से जाएगा,ना कि कर्मचारी की सैलरी से अतिरिक्त कटौती होगी। कंपनी के योगदान में से 8.33 फीसदी का योगदान पेंशन के तौर पर जमा किया जाएगा,बाकी पीएफ खाते में जमा किया जाएगा। इस फैसले से रिटायर्ड कर्मचारियों को एक रेगुलर इनकम की गारंटी होगी।

सक्षिप्त समाचार

अनंत नाग को दिग्गज अभिनेता को दादा साहब फाल्के सम्मान

नई दिल्ली,16 सितम्बर 2026। साल 2024 का दादासाहेब फाल्के पुरस्कार वरिष्ठ भारतीय कलाकार अनंत नाग को दिया जाएगा। यह सम्मान भारतीय सिनेमा में उनके शानदार योगदान और लंबे सिनेमाई सफर के लिए दिया जा रहा है। इस सम्मान को पाने के बाद पीएम मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है। इससे पहले साल 2025 में उन्हें पद्मभूषण से भी सम्मानित किया गया था। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में अभिनेता अनंत नाग को यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। इस समारोह का आयोजन 22 सितंबर 2026 को गुजरात के एकता नगर, केवड़िया में होगा। दादासाहेब फाल्के पुरस्कार चयन समिति की सिफारिश के बाद भारत सरकार ने अनंत नाग के नाम की घोषणा की है। अनंत नाग ने अपने लंबे करियर में अलग-अलग तरह के किरदार निभाए हैं और खास तौर पर कन्नड़ सिनेमा में उनका योगदान काफी अहम रहा है।

महाराष्ट्र में ट्रक से टकराई कार..चार लोगों की मौत, सात घायल

मुंबई,16 सितम्बर 2026। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मुंबई-नासिक हाईवे पर अटगांव के पास बुधवार को ट्रक और कार के बीच हुई टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई,जबकि 7 लोग घायल हैं। सभी घायलों को शाहपुर जिला उप अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस घटना की गहन छानबीन शाहपुर पुलिस स्टेशन की टीम कर रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस घटना के शिकार हुए सभी लोग मुंबई के जोगेश्वरी इलाके के रहने वाले थे। ये त्र्यंबकेश्वर में भगवान के दर्शन और पूजा-अर्चना करने के बाद बुधवार को मुंबई लौट रहे थे। इसी दौरान अटगांव के पास उनकी कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई। पुलिस ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला और शाहपुर उपजिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने चार लोगों को मृत घोषित कर दिया।

भारतीय युद्धपोत से भिड़ा पाकिस्तानी जहाज

दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक हलचल,भारत ने पाक राजनियक को किया तलब

नई दिल्ली,16 सितम्बर 2026। अरब सागर में अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र के भीतर भारतीय नौसेना के एक जहाज और पाकिस्तानी नौसेना के पोत की टक्कर के बाद भारत ने पाकिस्तान के प्रभारी राजनयिक को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारत के मुताबिक घटना में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ,लेकिन पाकिस्तानी नौसैनिक पोत का आचरण 1991 के भारत-पाकिस्तान समझौते के अनुच्छेद 10 के विपरीत था। भारत ने इस्लामाबाद में भी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के समक्ष विरोध दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।

भारतीय नौसेना के जहाज से हुई टक्कर

विदेश मंत्रालय ने कहा...'सीडीए को आज विदेश मंत्रालय में तलब किया गया और समुद्र में पाकिस्तानी नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य और गैर-पेशेवर आचरण को लेकर उनके समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया गया,जिसके कारण भारतीय नौसेना की एक इकाई से टक्कर हुई।'

अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में हुआ हादसा

विदेश मंत्रालय के अनुसार,यह घटना अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में हुई। हालांकि,टक्कर से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तानी नौसैनिक पोत का आचरण अप्रैल 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास,युद्धाभ्यास और सैनिकों की आवाजाही के लिए अग्रिम सूचना देने संबंधी समझौते के अनुच्छेद 10 का सीधे तौर पर उल्लंघन था।

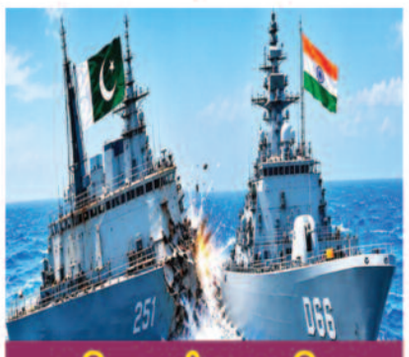

पाकिस्तानी राजनयिक को किया गया तलब

विदेश मंत्रालय ने बताया कि पाकिस्तानी प्रभारी राजनयिक को बुधवार को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया। उन्हें पाकिस्तानी अधिकारियों तक भारत की कड़ी आपत्ति पहुंचाने को कहा गया। भारत ने स्पष्ट किया कि समुद्र में सभी सैन्य इकाइयों को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए और दोनों देशों के बीच लागू संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करना चाहिए,ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो।

इस्लामाबाद में भी दर्ज कराया जाएगा विरोध

भारत ने इस मामले को केवल नई दिल्ली तक सीमित नहीं रखा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस्लामाबाद स्थित भारत के प्रभारी राजनयिक को भी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के समक्ष इसी तरह का विरोध दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है।

दोनों देशों की सैन्य इकाइयों से सावधानी बरतने की अपील

भारत ने इस घटना के माध्यम से सैन्य गतिविधियों के दौरान सावधानी और संबंधित समझौतों के पालन की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सभी सैन्य इकाइयों को समुद्र में उचित सावधानी बरतने और दोनों देशों के बीच लागू समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

भारत ने इस मामले में संयम बरता है...

इस घटना पर पूर्व नौसेना प्रवक्ता कैप्टन डी.के. शर्मा ने बताया कि समुद्र में पाकिस्तानी नौसैनिक जहाजों द्वारा एक भारतीय नौसैनिक जहाज के बेहद करीब आकर खतरनाक तरीके से टर्न करने की घटना पर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

सरकार बोली...यूपीआई पर चार्ज विदेशी दबाव में नहीं लगाया

राहुल ने कहा था...इससे अमेरिका को फायदा होगा फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

नई दिल्ली,16 सितम्बर 2026। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा...कि यूपीआई नियमों में बदलाव किसी विदेशी दबाव में नहीं लाया गया है। मंत्रालय ने कहा कि यूपीआईसे जुड़े फैसले भारत की घरेलू जरूरतों के आधार पर स्वतंत्र रूप से लिए गए हैं। एक अफसर ने बताया कि इस फैसले को पलटने का सवाल ही नहीं उठता। इससे पहले राहुल गांधी ने यूपीआईपर टैक्स लगाने के फैसले की आलोचना की थी। उन्होंने ट्वीट पर वीडियो जारी कर आरोप लगाया था कि इस फैसले से अमेरिका को फायदा होगा और सरकार को इसे वापस लेना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल....

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। इस याचिका में अदालत से सरकार के इस नए नियम को तुरंत रद्द करने की मांग की गई है। दरअसल,सरकार ने मंगलवार को आदेश दिया था कि 15 अक्टूबर 2026 से 2,000 से ज्यादा के चुनिंदा यूपीआईमर्चेंट पेमेंट पर 0.4% MDR लगेगा। इसकी अधिकतम सीमा 300 प्रति ट्रांजैक्शन होगी। यह शुल्क मर्चेंट से लिया जाएगा, ग्राहक से नहीं। 2,000 तक के यूपीआईपेमेंट और व्यक्ति से व्यक्ति ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं होगा।

जिरोधा के फाउंडर बोले...मर्चेंट और ब्रोकर के बीच बड़ा फर्क है

भारत की सबसे बड़ी स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी जिरोधा के फाउंडर और सीईओ नितिन कामथ ने कहा... कि यूपीआईका इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर होने लगा है, जिसके बाद एमडीआर शायद जरूरी हो,लेकिन इन्वेस्टिंग और ब्रोकिंग जैसे मामलों में मौजूदा एमडीआर फ्रेमवर्क प्रैक्टिकल नहीं लगता उनके मुताबिक,सामान्य मर्चेंट और ब्रोकर के बीच बड़ा फर्क है। नितिन ने उदाहरण देकर समझाया... अगर कोई ग्राहक 20,000 का सामान खरीदता है और यूपीआईसे भुगतान करता है,तो मर्चेंट को उसके बदले बिक्री से कमाई होती है। यानी पेमेंट सीधे कारोबार से जुड़ा है। लेकिन ब्रोकर के मामले में कस्टमर यूपीआईसे 2 लाख अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल सकता है और उस दिन एक भी शेयर नहीं खरीद सकता। ऐसे में ब्रोकर को ट्रांजैक्शन से कोई ट्रेडिंग रेवेन्यू नहीं मिला,लेकिन यूपीआईपेमेंट से जुड़ा एमडीआर खर्च उसके ऊपर आ सकता है।

पोखरण रेंज में वायु सेना के 'ड्रोनथॉन' ने दिखाई स्वदेशी ऑपरेशनल क्षमता

नई दिल्ली,16 सितम्बर 2026। घरेलू उद्योग को अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स (यूएएस) और काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स (सीयूएएस) में अपनी काबिलियत और तरक्की दिखाने के लिए भारतीय वायु सेना का 'आईएएफ ड्रोनथॉन' बुधवार को जैसलमेर के पोखरण रेंज में पूरा हुआ। नई ड्रोन और काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ-साथ उनकी ऑपरेशनल क्षमता देखने और आपसी सीख को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए डिजाइन किये गए इस इवेंट ने दिखाया कि तकनीक को ऑपरेशनल क्षमता में कैसे बदला जा सकता है। इस इवेंट में स्थिर प्रदर्शन और लाइव प्रदर्शन शामिल किये गए, जिससे आजकल के समाधान पहचानने और उनकी

लड़ाई में असरदार होने का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। इसमें सर्विलांस और टोही, ऑटोनॉमस ऑपरेशन, झुंड टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के क्षेत्र पर ध्यान दिया गया। 'आत्मनिर्भर भारत' के राष्ट्रीय विजन के साथ तालमेल बिठाते हुए ड्रोनथॉन-2026 का मकसद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, स्टार्ट-अप्स और इनोवेटर्स को जोड़कर स्वदेशी डिफेंस इकोसिस्टम को मजबूत करना था, ताकि वायु सेना तकनीकी रूप से उन्नत, स्वदेशी और भविष्य के लिए तैयार फोर्स बनाने के लिए चुनौतियों का सामना कर सके। भारतीय वायु सेना को तेजी से बदलते ऑपरेशनल माहौल में सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

बिहार में 50 लाख लोग बाढ़ में घिरे

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड,यूपी के लखीमपुर में 7 मकान नदी में बहे

नई दिल्ली,16 सितम्बर 2026। बिहार के 15 जिलों की 575 पंचायतों में करीब 50 लाख की आबादी अभी भी बाढ़ के पानी से घिरी हुई है। कटिहार में सरकारी स्कूल और कोचिंग सेंटर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बच्चे नाव में बैठकर पढ़ रहे हैं। प्रदेश के 26 जिलों बारिश का यलो अलर्ट है। आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। यूपी में बारिश से नदियां उफान पर हैं। 26 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। करीब 4 लाख की आबादी प्रभावित है। वहीं, लखीमपुर में शारदा नदी का कटान तेज होने से 24 घंटे में 7 मकान नदी में समा गए हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के आदि कैलाश मार्ग पर दोबाट में लैंडस्लाइड से सड़क फिर बंद हो गई। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग पर चीरबासा के पास सुरक्षा के मद्देनजर यात्रियों को हेलमेट पहनाकर भेजा जा

रहा है। चार दिन पहले लैंडस्लाइड में कई घोड़े-खच्चर मारे गए थे। रास्ते में पड़े शवों से बदबू और सांस लेने में परेशानी की शिकायतें सामने आ रही हैं। राजस्थान के 26 जिलों में 17 सितंबर तक बारिश का यलो अलर्ट है। मंगलवार को अजमेर, पाली समेत कुछ अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं, मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में 17 से 19 सितंबर तक और 18 से 21 सितंबर तक पूर्वी हिस्से में बारिश हो सकती है।

केंद्र ने यूएपीए के तहत शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया

नई दिल्ली,16 सितम्बर 2026। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान स्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क (एसबीएन) को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। सरकार ने गजट अधिसूचना जारी कर यूएपीए की पहली अनुसूची में संशोधन करते हुए शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठनों की सूची में क्रम संख्या 46 के रूप में शामिल किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर एक आधिकारिक पोस्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आतंकवाद के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति को आगे बढ़ाते हुए,गृह मंत्रालय ने शहजाद भट्टी नेटवर्क को यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है। शहजाद भट्टी नेटवर्क सीमा पार से हथियारों, विस्फोटकों और मादक पदार्थों की तस्करी के अलावा युवाओं तथा छोटे अपराधियों को आतंकवाद की ओर उकसाने में शामिल है। सिंडिकेट भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और सांप्रदायिक सौहार्द को निशाना बनाने के साथ नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित करता रहा है।

सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विकास के अगले चरण में उद्योग सक्रिय भागीदारी करे : पीएम मोदी

नई दिल्ली,16 सितम्बर 2026। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को सेमीकंडक्टर क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ गोलमेज बैठक में उद्योग जगत से भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विकास के अगले चरण में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया। मोदी ने सेवा तीर्थ में हुई बैठक में कहा कि भारत को उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में शुरुआती अग्रणी देशों में शामिल होने का लक्ष्य रखना चाहिए। उन्होंने कहा...कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और अब भारत का पारिस्थितिकी तंत्र बुनियादी प्रयासों से आगे बढ़कर बड़े स्तर और नए अवसरों के चरण में प्रवेश कर रहा है। प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के भविष्य को आकार देने के लिए सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच करीबी सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि भारत के पास प्रतिभा,प्रौद्योगिकी को अपनाने की क्षमता और बुनियादी ढांचे की मजबूत नींव है। उन्होंने उद्योग से कौशल विकास,नवाचार तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती

प्रौद्योगिकियों में अधिक भागीदारी करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने एआई में एक करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत की प्रतिभा और वैश्विक उद्योग जगत के नेताओं के अनुभव एवं क्षमताओं के मेल से बड़े अवसर पैदा किए जा सकते हैं। मोदी ने कहा कि तकनीकी बदलाव और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियों में भी बदलाव होना चाहिए। उन्होंने उद्योग जगत के नेताओं से नीतिगत और प्रशासनिक उपायों को लेकर सुझाव देने का आग्रह किया तथा कहा कि क्षेत्र को और मजबूत करने में उनके सुझावों पर उचित विचार किया जाएगा। बैठक में शामिल सीईओ और अन्य प्रतिनिधियों ने भारत की सेमीकंडक्टर क्षमताओं को विकसित करने के लिए सरकार के लगातार प्रयासों की सराहना की। उन्होंने विनिर्माण, डिजाइन, बुनियादी ढांचे और प्रतिभा विकास के क्षेत्र में हुई प्रगति का उल्लेख किया तथा 'आईएसएम 2.0' के तहत उभरते अवसरों को लेकर विश्वास जताया। कंपनियों के प्रतिनिधियों ने सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास, उन्नत प्रौद्योगिकियों और सहायक उद्योगों सहित विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता विकसित करने की भारत की संभावनाओं पर भी भरोसा जताया। उन्होंने भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी सेमीकंडक्टर एवं प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने में योगदान देने की प्रतिबद्धता जताई। बैठक में सेमी,माइक्रोन,इन्फिनियॉन,एप्लाइड मैटेरियल्स,एएसएमएल,मर्क,टोक्योइलेक्ट्रॉन, फुजी फिल्म,एएमडी,इंटेल,टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स,लैम रिसर्च,रैपिडस,एनएक्सपी, फॉक्सकॉन,सेमीकंडक्टर डिवाइसेज, एडवांटेस्ट,सेलेस्टा कैपिटल,सीजी पावर और आईबीएम रिसर्च समेत विभिन्न संगठनों के प्रमुख और प्रतिनिधि शामिल हुए।

संपादकीय

75 वर्ष की उम्र में मोदी : उपलब्धियां,चुनौतियां और नेतृत्व का सवाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन देश के राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अवसर है। 17 सितंबर 1950 को जन्मे नरेंद्र मोदी 75 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं। वर्ष 2014 से देश का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कई बड़े फैसले हुए। इन फैसलों ने देश की राजनीति,अर्थव्यवस्था और प्रशासन को प्रभावित किया। ऐसे में जन्मदिन के अवसर पर उनके कार्यकाल का मूल्यांकन केवल उपलब्धियों की चर्चा तक सीमित नहीं होना चाहिए,बल्कि चुनौतियों और भविष्य के सवालों पर भी विचार होना चाहिए। मोदी सरकार के कार्यकाल में जनधन योजना,उज्ज्वला योजना,स्वच्छ भारत मिशन,प्रधानमंत्री आवास योजना,आयुष्मान भारत और डिजिटल भुगतान जैसी योजनाओं को प्रमुखता मिली। सड़क,रेल,हवाई अड्डे और डिजिटल ढांचे के विस्तार पर भी जोर दिया गया। सरकार इन पहलों को विकास और जनकल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां बताती है। इन योजनाओं से अनेक लोगों को लाभ मिला है,लेकिन यह देखना भी जरूरी है कि सरकारी सुविधाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक कितना पहुंचा। नोटबंदी,जीएसटी और अन्य आर्थिक फैसलों ने देश की आर्थिक व्यवस्था में बदलाव किए। इन निर्णयों को लेकर सरकार और विपक्ष के अपने-अपने तर्क रहे हैं। किसी भी नीति का वास्तविक मूल्यांकन उसके घोषित उद्देश्य के साथ-साथ उसके परिणामों से होना चाहिए। रोजगार, महंगाई,छोटे कारोबार और आम परिवारों की आर्थिक स्थिति जैसे सवाल आज भी महत्वपूर्ण हैं।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की वैश्विक भूमिका और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सक्रियता बढ़ी है। देश ने बुनियादी ढांचे और तकनीक के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इसके साथ ही सामाजिक सद्भाव, संस्थाओं की स्वतंत्रता, संसद में सार्थक चर्चा और नागरिकों के अधिकार जैसे विषयों पर भी निरंतर ध्यान देना आवश्यक है। लोकतंत्र में सरकार की उपलब्धियों की प्रशंसा के साथ उसकी नीतियों पर सवाल उठाने की जगह भी बनी रहनी चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 वर्ष की उम्र में पद छोड़ने की चर्चा भी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की उम्र संबंधी नीति को लेकर समय-समय पर सवाल उठे हैं। हालांकि, प्रधानमंत्री पद छोड़ने की कोई अनिवार्य संवैधानिक व्यवस्था या ऐसी निश्चित आधिकारिक घोषणा सामने नहीं है। इसलिए इस विषय को तथ्य के रूप में नहीं,बल्कि राजनीतिक चर्चा के रूप में ही देखा जाना चाहिए। नेतृत्व का सवाल केवल उम्र से तय नहीं होता। लोकतंत्र में जनता का जनादेश, संवैधानिक व्यवस्था,राजनीतिक दलों के नियम और नेतृत्व की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी नेता के भविष्य को लेकर अंतिम निर्णय संबंधित राजनीतिक प्रक्रिया और संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए।

प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल में देश के सामने रोजगार,महंगाई, शिक्षा,स्वास्थ्य,किसानों की आय और सामाजिक समरसता जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। विकास के बड़े दावों के साथ यह भी जरूरी है कि गांवों की सड़कें,सरकारी अस्पताल,स्कूल और आम नागरिक की रोजगारी की समस्याएं प्राथमिकता में रहें। विकास का अर्थ तभी पूरा होगा,जब उसका लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। उनके कार्यकाल की उपलब्धियों को स्वीकार करना और कमियों पर सवाल उठाना, दोनों लोकतांत्रिक अधिकार हैं। देश को मजबूत नेतृत्व के साथ मजबूत संस्थाएं, पारदर्शी शासन और जनता के प्रति जवाबदेही भी चाहिए। जन्मदिन का अवसर केवल शुभकामनाओं का नहीं,बल्कि यह याद दिलाने का भी है कि सत्ता जनता की सेवा का माध्यम है। सरकार किसी भी दल की हो,उसकी सबसे बड़ी कसौटी आम नागरिक का विश्वास और उसके जीवन में आया वास्तविक बदलाव होना चाहिए।

हर मरीज की बेहतर स्वास्थ्य सुविधा सुरक्षा तक पहुंच

डॉ.प्रितम भि.गेडाम
नई दिल्ली

अभी हाल ही में समाचारपत्रों में एक खबर पढ़ी थी,कोटा राजस्थान की 15 वर्षीय तन्वी परियानी नामक लड़की गंभीर हृदय रोग से पीड़ित थी,वर्ष 2014 से 13 साल तक एम्स दिल्ली में ऑपरेशन की राह देखते-देखते 1 सितंबर को उसका देहांत हो गया,इन 13 सालों में तन्वी के परिवार के लाखों रुपये खर्च हुए, ऑपरेशन की नई तारीखे मिलती रही, लेकिन ऑपरेशन नहीं हुआ। तन्वी के पिता ने अस्पताल पर दोष लगाया और कहा कि,गरीब हूँ,लेकिन बेटी के मौत के बाद भी न्याय के लिए लड़ता रहूँगा। तन्वी के मौत के बाद एम्स ने इलाज और मौत के मामले की समीक्षा के लिए जाँच समिति गठित की हैं। भारत देश गांवों में बसता है,क्योंकि बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है,लेकिन रोजाना ग्रामीण क्षेत्र में होनेवाली अनेक हृदय विदारक घटनाएं इंसानियत को शर्मसार कर देते हैं। मध्यप्रदेश के बालाघाट के आदिवासी क्षेत्र के 30 से ज्यादा बच्चों के मौत की खबरों ने विचलित कर दिया,ऐसी दुःखद घटनायें स्वास्थ्य सुविधा सुरक्षा पर सीधे सवाल खड़े करती हैं। अभी हाल ही में तेलंगाना के कोलमगुडा ग्रामीण भाग में सात महीने की गर्भवती महिला गंभीर रूप से बीमार पड़ गई,खराब सड़क और कोई सुविधा न होने के कारण गांव के लोगों ने उफनती हुयी नदी पार करके कामचलाऊ स्ट्रेचर बनाकर उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया। यह केवल एक घटना नहीं है,रोजाना ऐसी अनेक घटनाएं गांवों में घटित होती है,बहुत से भागों में सड़कें तक नहीं होती,कि स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंच सकें। वक्त पर उपचार न मिलने के कारण हर साल बड़ी संख्या में लोग जान गवाते हैं। ग्रामीण भागों के स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी तो अक्सर बनी ही रहती है,अत्याधुनिक सेवा-सुविधा तो जैसे सपना ही हैं।

हर साल 17 सितंबर को दुनियाभर में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और सुरक्षा मिलें,इसलिए विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता हैं। इस साल 2026 की थीम गैर-संचारी रोगों के लिए सुरक्षित देखभाल है एवं इसका आधिकारिक नारा जीवन के लिए सुरक्षित देखभाल यह हैं। भारत देश में मरीज सुरक्षा के सामने स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे पर अत्यधिक बोझ, कर्मचारियों की भारी कमी,अत्याधुनिक संसाधनों की कमी और रोगी-सेवा प्रदाता के बीच उच्च अनुपात जैसी बड़ी चुनौतियां हैं। हमारे देश में जनसंख्या के मुकाबले स्वास्थ्य चिकित्सकों की भारी कमी है,भले ही महानगरों और शहरों में पांच सितारा होटल जैसे नवनवीन निजी अस्पतालों का शुभारंभ हो रहा है,सरकार की ओर से भी चिकित्सा सेवा को मजबूत बनाने में जोर दिया जा रहा है, फिर भी अत्यधिक बढ़ती बीमारियां देश की आबादी पर तेजी से शिकंजा कस रही है,इसमें गरीब और मध्यम वर्ग विशेषत ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को संघर्ष करना पड़ता है। एम्बुलेंस के लिए पैसे न होने के कारण अपनों के लाशों को कंधे पर ढोते परिजन को हमने बहुत बार देखा हैं। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में हुई कुल मौतों में से लगभग आधी मौतें किसी प्रशिक्षित व्यावसायिक की मेडिकल देखरेख के बिना हुई। 2024 में ऐसी मौतों का हिस्सा 45.5 प्रतिशत था,जो 2020 में दर्ज 18 फीसदी से दोगुने से भी ज़्यादा है और 2021 से यह कुल मौतों के लगभग आधे के बराबर बना हुआ हैं। इस श्रेणी में वे लोग शामिल हैं

जिन्हें मृत्यु के समय कोई चिकित्सा सहायता नहीं मिली,या जिनकी देखभाल केवल एक अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा की गई थी। 2024 में,प्रशिक्षित चिकित्सा देखभाल के बिना होने वाली मौतों का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में काफी अधिक,48.9 प्रतिशत,शहरी क्षेत्रों में, 36.1 फीसदी था।

विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुसार, स्वास्थ्य देखभाल के दौरान हर 10 में से लगभग 1 मरीज़ को नुकसान पहुँचता है और असुरक्षित देखभाल के कारण हर साल 30 लाख से ज़्यादा मौतें होती हैं। कम और मध्यम आय वाले देशों में, असुरक्षित देखभाल के कारण हर 100 में से 4 लोगों की मौत हो जाती हैं। 50 फीसदी से ज़्यादा नुकसान को रोका जा सकता है,इस नुकसान का आधा हिस्सा दवाओं से जुड़ी समस्याओं के कारण होता हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार, प्राइमरी और एम्बुलेटरी सेटिंग्स में हर 10 में से 4 मरीज़ों को नुकसान पहुँचता है,जबकि इस नुकसान में से 80 फीसदी तक को रोका जा सकता हैं। जैसे : दवा से जुड़ी गलतियाँ,असुरक्षित सर्जिकल प्रक्रियाएँ,हेल्थ केयर से जुड़े संक्रमण, जाँच या डायग्नोसिस में गलतियाँ, मरीज़ का गिरना,प्रेशर अल्सर,मरीज़ की गलत पहचान,असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन और वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। मरीज़ को होने वाले नुकसान से ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में कमी आ सकती हैं। ग्लोबल स्तर पर,इस नुकसान की अप्रत्यक्ष लागत हर साल खरबों अमेरिकी डॉलर होती हैं।

हेल्थवॉइस-मेडिसर्कल मीडिया वेंचर जर्नल में प्रकाशित रिसर्च कहती है कि, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जटिल स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में से एक होने के नाते,भारत पर इस बोझ का एक बड़ा हिस्सा हैं। 18वीं सालाना मेडलीगल रिव्यू के अनुसार,अकेले 2025 में भारत में मेडिकल लापरवाही के 65,000 मामले दर्ज किए गए। ऐसे मामलों से सामने आए जोखिम एक बड़ी वैश्विक समस्या को दर्शाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि,असुरक्षित मेडिकल देखभाल के कारण हर साल अनुमानित 138 मिलियन मरीज़ों को नुकसान पहुँचता हैं।

आजकल हर क्षेत्र में नकली उत्पाद की भरमार है;दवा बाजार भी इससे अछूता नहीं। नकली दवाओं का साम्राज्य तेजी से फलफूल रहा हैं। नकली दवाओं के नेटवर्क और उत्पादन में तेज़ी से हो रही बढ़ोतरी के कारण,नकली दवाओं को रोकने वाली पैकेजिंग का ग्लोबल मार्केट 2026 में 129 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाओं का जखीरा मिलने की वारदातें भी हो चुकी हैं। कुछ समय पहले ही सरकारी नागपुर मेडिकल महाविद्यालय व अस्पताल में यह पुष्टि हुई थी।

एक दौर था,जब चिकित्सक हाथों की नब्ज,आंखे,जबान देखकर ही बीमारियों का पता लगाते थे,शायद ही कभी टेस्ट करते थे। लेकिन आज चिकित्सालय में जाने पर अधिकतर बार पहले टेस्ट लिखकर दिया जाता है,फिर रिपोर्ट आने पर इलाज होता हैं। बहुत बार तो टेस्ट कहा करना और दवा कहा से लेना है यह भी तय होता हैं। चिकित्सक सरकारी अस्पतालों में सेवा देने के बजाय निजी अस्पतालों में कार्य को प्राथमिकता देते हैं। अधिकतर पाश्चिमात्य और विकसित देशों में चिकित्सक को कड़े कानून के तहत पूरी ईमानदारी और कौशल से स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य करने पड़ते है, मरीज के इलाज के दौरान थोडीसी भी गलती या लापरवाही पर चिकित्सक को जिम्मेदार ठहराते हुए उनका लाइसेंस जप्त किया जाता है और सजा दी जाती हैं। लेकिन हमारे देश में इलाज के दौरान होनेवाली लापरवाही पर ऐसी जवाबदेही तय नहीं है जो पारदर्शकता दर्शाये।

बाकी क्षेत्रों की तरह ही स्वास्थ्य क्षेत्र में भी धोखाधड़ी,भ्रष्टाचार,जालसाजी और अनैतिकता की घटनाओं के बारे में खबरें देखने-सुनने को मिलती हैं। सोशल मीडिया के दौर में तो आये दिन इस क्षेत्र के वीडियो वायरल होते हैं। लेकिन दुनिया में केवल यही एक ऐसा क्षेत्र है,जहां चिकित्सक को अमूल्य जान बचानेवाले भगवान का दर्जा दिया जाता हैं। हर मरीज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा बेहद सहज ढंग से मिलनी चाहिए। केवल पैसों की कमी की वजह से किसी भी मासूम को जान गवाना ना पड़े। ग्रामीण,दूर-दराज,पिछड़े इलाकों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं की पकड़ मजबूत होनी चाहिए। सबको स्वास्थ्य सुविधा का अधिकार है,तो हर एक तक उसकी पहुंच भी होनी चाहिए।

सृष्टि के पहले इंजीनियर माने जाते है भगवान विश्वकर्मा

रमेश सर्राफ धमोरा
झुंझुनू,राजस्थान

विश्वकर्मा पूजा भारत में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन देश भर में स्थित कारखानों, कार्यशालाओं और विभिन्न कार्यस्थलों पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ताकि श्रम और कौशल का सम्मान किया जा सके और आने वाले वर्ष के लिए आशीर्वाद प्राप्त हो सके। हर साल विश्वकर्मा पूजा कन्या संक्रांति के दिन मनाई जाती है। इस दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। इसलिए इसे विश्वकर्मा जयंती भी कहते हैं।

विश्वकर्मा पूजा एक ऐसा त्योहार है जहां शिल्पकार, कारीगर,श्रमिक भगवान विश्वकर्मा का त्योहार मनाते हैं। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा के पुत्र विश्वकर्मा ने पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया था। विश्वकर्मा को देवताओं के महलों का वास्तुकार भी कहा जाता है। विश्वकर्मा दो शब्दों विश्व (संसार या ब्रह्मांड) और कर्म (निर्माता) से मिलकर बना है। इसलिए विश्वकर्मा शब्द का अर्थ है दुनिया का निर्माण करने वाला। भगवान विश्वकर्मा को निर्माण एवं सृजन का देवता माना जाता है। हिंदू धर्म में इन्हें सृष्टि के दिव्य शिल्पकार, देवताओं के वास्तु विशेषज्ञ और पहले इंजीनियर के रूप में पूजा जाता है।

विश्वकर्मा रचनात्मकता,तकनीकी कौशल और नवाचार के प्रतीक हैं। उनके सम्मान में भाद्रपद मास की सूर्यकन्या संक्रांति पर विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। यह वह दिन है जब सूर्य सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करता है। इस दिन मजदूर, कारीगर, इंजीनियर,आर्किटेक्ट और उद्योगपति अपने औजारों और मशीनों की पूजा करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चार युगों में विश्वकर्मा जी ने कई नगर और भवनों का निर्माण किया था।

विश्वकर्मा शिल्पशास्त्र के आविष्कारक और सर्वश्रेठ ज्ञाता माने जाते हैं। जिन्होने विश्व के प्राचीनतम तकनीकी ग्रंथों की रचना की थी। इन ग्रंथों में न केवल भवन वास्तु विद्या,रथ आदि वाहनों के निर्माण बल्कि विभिन्न रत्नों के प्रभाव व उपयोग आदि का भी विवरण है। माना जाता है कि उन्होनें ही देवताओं के विमानों की रचना की थी। भगवान विश्वकर्मा की उत्पत्ति ऋग्वेद में हुई है। जिसमें उन्हें ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में वर्णित किया गया है। भगवान विष्णु और शिवलिंग की नाभि से उत्पन्न भगवान ब्रह्मा की अवधारणाएं विश्वकर्मण सूक्त पर आधारित हैं। विश्वकर्मा प्रकाश को वास्तुतंत्र का अपूर्व ग्रंथ माना जाता है। इसमें अनुपम वास्तुविद्या को गणितीय सूत्रों के आधार पर प्रमाणित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि सभी पौराणिक संरचनाए भगवान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित हैं। भगवान विश्वाकर्मा के जन्म को देवताओं और राक्षसों के बीच हुए समुद्र मंथन से माना जाता है। पौराणिक युग के

अस्त्र और शस्त्र भगवान विश्वकर्मा द्वारा ही निर्मित हैं।

विश्वकर्मा को सृष्टि के रचयिता ब्रह्माजी का वंशज माना गया है। ब्रह्माजी के पुत्र धर्म तथा धर्म के पुत्र वास्तु देव थे। जिन्हें शिल्पशास्त्र का आदि पुरुष माना जाता है। इन्हीं वास्तु देव की अंगिरसी नामक पत्नी से विश्वकर्मा का जन्म हुआ। अपने पिता के पद चिन्हों परचलते हुए विश्वकर्मा भी वास्तुकला के महान आचार्य बने। मनु,मय,त्वष्टा,शिल्पी और देवज्ञ इनके पुत्र हैं। इन पांचों पुत्रों को वास्तुशिल्प की अलग-अलग विधाओं में विशेषज्ञ मानाजाता है।

विश्वकर्मा वैदिक देवता के रूप में सर्वमान्य हैं। इनको गृहस्थ आश्रम के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माता और प्रवर्तक भी कहा गया है। अपने विशिष्ट ज्ञान-विज्ञान के कारण देवशिल्पी विश्वकर्मा मानव समुदाय ही नहीं वरन देवगणों द्वारा भी पूजित हैं। देवता,नर,असुर, यक्ष और गंधर्व सभी में उनके प्रति सम्मान का भाव है। भगवान विश्वकर्मा के पूजन-अर्चना किये बिना कोई भी तकनीकी कार्य शुभ नहीं माना जाता। इसी कारण विभिन्न कार्यो में प्रयुक्त होनेवाले औजारों,कल-कारखानों और विभिन्न उद्योगों में लगी मशीनों का पूजन विश्वकर्मा जयंती पर किया जाता है। पौराणिक साक्ष्यों के मुताबिक स्वर्ग लोक की इन्द्रपुरी,यमपुरी,वरुणपुरी,कुबेरपुरी,असुर राजरावण की स्वर्णनगरी लंका,भगवान श्रीकृष्णकी समुद्र नगरी द्वारिका और पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर के निर्माण का श्रेय भी विश्वकर्मा को ही जाता है। पौराणिक कथाओं में इन उत्कृष्ट नगरियों के निर्माण के रोचक विवरण मिलते हैं। उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर तो विश्वकर्मा के शिल्प कौशल का अप्रतिम उदाहरण माना जाता है। विष्णु पुराण में उल्लेख है कि जगन्नाथ मंदिर की अनुपम शिल्प रचना से खुश होकर भगवान विष्णु ने उन्हे शिल्पावतार के रूप में सम्मानित किया था।

महाभारत में पांडव जहां रहते थे उस स्थान को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। इसका निर्माण भी विश्ववकर्मा ने किया था। कौरव वंश के हस्तिनापुर और भगवान कृष्ण के द्वारका का निर्माण भी विश्वणकर्मा ने ही किया था। सतयुग का स्वर्ग लोक,त्रेतायुग की लंका, द्वापर की द्वारिका और कलयुग के हस्तिनापुर आदि के रचयिता विश्वकर्मा जी की पूजा अत्यन्त शुभकारी है। सृष्टि के प्रथम सूत्रधार, शिल्पकार और विश्व के पहले तकनीकी ग्रन्थ के रचयिता भगवान विश्वकर्मा ने देवताओं की रक्षा के लिये अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण किया था।

विष्णु को चक्र,शिव के त्रिशूल,इंद्र को वज्र,हनुमान को गदा और कुबेर को पुष्पक विमान विश्वकर्मा ने ही प्रदान किये थे। सीता स्वयंवर में जिस धनुष को श्रीराम ने तोड़ा था वह भी विश्वकर्मा के हाथों बना था। जिस रथ पर निर्भर रहकर श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन संसार को भस्म करने की शक्ति रखते थे उसके निर्माता विश्वकर्मा ही थे। पार्वती के विवाह के लिए जो मण्डप और वेदी बनाई गई थी वह भी विश्वकर्मा ने ही तैयार की थी।

मनी लॉन्ड्रिंग : अपराध की काली कमाई को सफेद करने का खेल

डॉ. सत्यवान सौरभ
भिवानी,हरियाणा

मनी लॉन्ड्रिंग अर्थात धनशोधन आज केवल आर्थिक अपराध नहीं रह गया है, बल्कि यह संगठित अपराध,भ्रष्टाचार, मादक पदार्थों की तस्करी,आतंकवाद और अवैध व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय आधार बन चुका है। सामान्य शब्दों में कहें तो मनी लॉन्ड्रिंग वह प्रक्रिया है,जिसके माध्यम से अपराध से अर्जित धन के वास्तविक स्रोत को छिपाकर उसे वैध अथवा कानूनी रूप से अर्जित धन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अपराधी जानते हैं कि केवल अवैध तरीके से धन कमाना पर्याप्त नहीं है;उस धन को ऐसी व्यवस्था में शामिल करना भी आवश्यक है,जिससे उसकी वास्तविक उत्पत्ति का पता लगाना कठिन हो जाए। यही कारण है कि आधुनिक वित्तीय व्यवस्था में धनशोधन की चुनौती लगातार जटिल होती जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया को सामान्यतः तीन प्रमुख चरणों में समझा जाता है...प्लेसमेंट,लेयरिंग और इंटीग्रेशन। पहले चरण में अपराध से प्राप्त धन को वित्तीय व्यवस्था में प्रवेश कराया जाता है। इसे प्लेसमेंट कहा जाता है। उदाहरण के लिए,बड़ी मात्रा में प्राप्त अवैध नकदी को अलग-अलग बैंक खातों में जमा करना,छोटी-छोटी रकम में विभाजित करके लेन-देन करना या नकदी आधारित व्यवसायों के माध्यम से उसे वित्तीय प्रणाली में शामिल करना इसके तरीके हो सकते हैं। अपराधी इस चरण में विशेष रूप से इसलिए सावधानी बरतते हैं क्योंकि यहीं अवैध धन और वित्तीय व्यवस्था के बीच पहला संपर्क स्थापित होता है।

दूसरे चरण को लेयरिंग कहा जाता है। इसका उद्देश्य धन के वास्तविक स्रोत को छिपाना और जांच एजेंसियों के लिए उसके रास्ते को जटिल बनाना होता है। इसके लिए अनेक बैंक खातों,कंपनियों,मध्यस्थ संस्थाओं और वित्तीय लेन-देन का इस्तेमाल किया जा सकता है। धन को एक खाते से दूसरे खाते,एक कंपनी से दूसरी कंपनी अथवा एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित किया जा सकता है। कई बार कागजों पर मौजूद कंपनियों या जटिल व्यावसायिक लेन-देन के माध्यम से धन की ऐसी परतें बनाई जाती हैं कि उसके मूल स्रोत तक पहुंचना कठिन हो जाए। डिजिटल वित्तीय व्यवस्था ने जहां लेन-देन को आसान बनाया है,वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धन के तेज आवागमन ने अपराधियों के लिए नई चुनौतियों और नए अवसरों दोनों को जन्म दिया है।

तीसरा चरण इंटीग्रेशन अर्थात एकीकरण है। इस चरण में धन को इस प्रकार अर्थव्यवस्था में वापस लाया जाता है कि वह वैध आय या निवेश जैसा दिखाई देने लगे। अपराध से अर्जित धन का इस्तेमाल संपत्ति खरीदने,व्यापार में निवेश करने, कंपनियों में पूंजी लगाने या अन्य वैध आर्थिक गतिविधियों में किया जा सकता है। एक बार धन वैध आर्थिक गतिविधियों का हिस्सा बन जाता है तो उसके आपराधिक स्रोत की पहचान करना और भी मुश्किल हो सकता है। इस प्रकार अपराध से अर्जित धन धीरे-धीरे वैध अर्थव्यवस्था में घुलने लगता है।

मनी लॉन्ड्रिंग की सबसे बड़ी चिंता यह है कि यह अपराध और अर्थव्यवस्था के बीच एक खतरनाक पुल का काम करता है। यदि अपराध से प्राप्त धन को आसानी से वैध बनाया जा सके तो अपराधियों को अपनी गतिविधियां जारी रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। भ्रष्टाचार से अर्जित धन,मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त आय,अवैध खनन, धोखाधड़ी,तस्करी और संगठित अपराध से जुड़ी कमाई को धनशोधन के माध्यम से छिपाया जा सकता है। इसके कारण अपराध की आर्थिक नींव मजबूत होती है और कानून का शासन कमजोर पड़ता है। धनशोधन वित्तीय संस्थाओं की विश्वसनीयता को भी प्रभावित करता है। बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं यदि अवैध धन के प्रवाह को पहचानने और रोकने में असफल रहती हैं तो पूरी वित्तीय व्यवस्था की पारदर्शिता पर प्रश्न खड़े होते हैं। इसके अलावा, बड़े पैमाने पर अवैध धन का प्रवाह बाजार में प्रतिस्पर्धा को विकृत कर सकता है। ईमानदारी से कारोबार करने वाले व्यक्ति और संस्थाएं उन लोगों से पिछड़ सकते हैं, जिनके पास अपराध से अर्जित पूंजी उपलब्ध है। इस तरह धनशोधन केवल कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं, बल्कि आर्थिक न्याय और वित्तीय स्थिरता का भी प्रश्न है।

भारत ने धनशोधन से निपटने के लिए एक व्यापक कानूनी और संस्थागत ढांचा विकसित किया है। धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 इसका प्रमुख कानूनी आधार है। इस कानून का उद्देश्य अपराध से अर्जित आय की पहचान,जांच,कुर्की और परिस्थितियों के अनुसार जब्ती की प्रक्रिया को सक्षम बनाना है। यह कानून उन गतिविधियों पर कार्रवाई का आधार प्रदान करता है, जिनके माध्यम से अपराध से प्राप्त संपत्ति को छिपाने,रखने,उपयोग करने या उसे वैध दिखाने का प्रयास किया जाता है।

इस कानून के क्रियान्वयन में प्रवर्तन निदेशालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रवर्तन निदेशालय धनशोधन से जुड़े मामलों की जांच करता है तथा अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाने और उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाता है। दूसरी ओर, वित्तीय खुफिया इकाई-भारत संदिग्ध वित्तीय लेन-देन से संबंधित सूचनाओं का विश्लेषण करती है। वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त सूचनाओं के विश्लेषण के माध्यम से संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करना धनशोधन विरोधी व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

वित्तीय संस्थाओं के लिए अपने ग्राहक को जानो अर्थात केवाईसी व्यवस्था भी इस लड़ाई का महत्वपूर्ण उपकरण है। ग्राहक की पहचान और वित्तीय गतिविधियों की निगरानी से संदिग्ध खातों तथा असामान्य लेन-देन की पहचान में मदद मिलती है। संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्टिंग संबंधी दायित्व भी वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाते हैं। हालांकि केवल नियम बना देना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि इन नियमों का पालन प्रभावी,समान और तकनीकी रूप से सक्षम तरीके से हो।

धनशोधन की प्रकृति सीमा-पार होने के कारण अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी अत्यंत आवश्यक है। अपराधी एक देश में धन अर्जित करके दूसरे देश में उसे स्थानांतरित कर सकते हैं और तीसरे देश में निवेश कर सकते हैं। इसलिए भारत को अन्य देशों,अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं और संबंधित जांच एजेंसियों के साथ सूचना साझा करने,संदिग्ध लेन-देन का पता लगाने और अवैध संपत्तियों की पहचान करने में सहयोग बढ़ाना होगा। वैश्विक स्तर पर धनशोधन के विरुद्ध सहयोग जितना मजबूत होगा, अपराधियों के लिए वित्तीय व्यवस्था का दुरुपयोग करना उतना ही कठिन होगा। फिर भी चुनौती समाप्त नहीं हुई है। डिजिटल भुगतान,आभासी संपत्तियां, जटिल कॉरपोरेट संरचनाएं और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेन-देन ने धनशोधन के तौर-तरीकों को लगातार बदल दिया है। इसलिए भारत को तकनीक आधारित वित्तीय निगरानी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विश्लेषण जैसी आधुनिक क्षमताओं का जिम्मेदारी से उपयोग बढ़ाना होगा। साथ ही,जांच एजेंसियों की क्षमता,विशेषज्ञता और विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय को मजबूत करना भी आवश्यक है।

अंततः मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध लड़ाई केवल अपराधियों की संपत्ति जब्त करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसका वास्तविक उद्देश्य अपराध से होने वाले आर्थिक लाभ को समाप्त करना होना चाहिए। जब अपराधी को यह विश्वास हो जाएगा कि अवैध कमाई को सुरक्षित रूप से वैध धन में बदलना आसान नहीं है,तभी अपराध की आर्थिक संरचना पर प्रभावी प्रहार होगा। मजबूत कानून,सक्षम संस्थाएं,सतर्क वित्तीय प्रणाली,आधुनिक तकनीक,पारदर्शिता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग—इन सभी के समन्वित प्रयास से ही भारत अपराध की काली कमाई को वैध अर्थव्यवस्था में प्रवेश करने से प्रभावी रूप से रोक सकता है।

कोई समझता नहीं

केशी गुप्ता
द्वारका दिल्ली

तू समझता नहीं मुझे
हर कोई एक दूसरे से कहता है
ये एक ख्याल जनाब
हर किसी के दिल में रहता है
कोई समझ ले मुझे
कोई तो पहचान ले
मेरी हर बात को
बिना कहे ही जान ले
जो कहना चाहता हूं
कोई तो सुन ले उसे
बिना किसी विश्लेषण के
समझे मेरे विचारों को
ना रोके न टोके कोई
बहने दे मेरे ख्वाबों को
लेने दे उड़ान मुझे
छू लेने दे आसमान मुझे
दर्द मेरा जो बाँट ले
बहने दे आंसू मेरे
समझाये नहीं कुछ भी
समझ ले हर बात को
मिलेगा कहां वो शख्स
जो खेले ना जज़्बातों से
जिस से कह दूं सब कुछ मैं
बिना किसी संकोच के
बड़ी विकट समस्या है
हर एक पर है लागू
हर कोई भरा बैठा है भीतर
ढूंढ रहा उस इंसान को
सब को लगता है भैया
कोई मझता नहीं है मुझको

सूचना
समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
सम्पादक

सरगुजा में कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन : सात सत्रों में संगठन, धर्मनिरपेक्षता से लेकर आदिवासी मुद्दों और सोशल मीडिया तक मंथन

भूपेश बघेल,ताम्रध्वज साहू और राजेश तिवारी ने संभाले अलग-अलग सत्र

दीपक बैज ने बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर दिया जोर,अंतिम दिन चरणदास महंत करेंगे प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित

-संवाददाता-
अंबिकापुर,16 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा संभाग में कांग्रेस के तीन दिवसीय संभाग स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन बुधवार को संगठन निर्माण से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया, सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक चले प्रशिक्षण में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल,पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू,एआईसीसी सचिव राजेश तिवारी,प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज सहित विशेषज्ञ प्रशिक्षकों ने अलग-अलग सत्रों में ब्लॉक अध्यक्षों और मास्टर ट्रेनरों को संबोधित किया। दूसरे दिन कुल सात सत्र आयोजित किए गए,सरगुजा संभाग के छह जिलों के 49 संगठनात्मक ब्लॉक अध्यक्ष और 12 मास्टर ट्रेनर इस प्रशिक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं,तीन दिवसीय शिविर का उद्देश्य संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करते हुए प्रशिक्षण को आगे मंडल और बूथ स्तर तक पहुंचाना बताया गया है।

भगवान गणेश की पूजा से हुई दूसरे दिन की शुरुआत

प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सहित सभी प्रशिक्षकों और प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण स्थल पर स्थापित भगवान गणेश की पूजा-अर्चना के साथ सत्रों की शुरुआत की,इसके बाद संगठनात्मक गतिविधियों के साथ दिनभर अलग-अलग विषयों पर प्रशिक्षण और संवाद का दौर चला, सुबह 7 बजे कांग्रेस सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष अरुण ताम्रकार,सरगुजा संभाग प्रभारी विनीत विशाल जायसवाल और जिला कांग्रेस अध्यक्ष लोकेश कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस ध्वज फहराया गया,इसके बाद करीब एक घंटे तक योग प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें योग प्रशिक्षक अजय तिवारी ने प्रशिक्षणार्थियों को योगाभ्यास कराया।

सत्ता और संगठन के बीच समन्वय पर ताम्रध्वज साहू ने दिया प्रशिक्षण

पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने'सत्ता और संगठन में समन्वय' विषय पर प्रशिक्षण दिया, उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय रहने से जनता की अपेक्षाओं और समस्याओं को शासन तक पहुंचाने तथा उनके समाधान की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है,उन्होंने संगठन के छोटे से छोटे कार्यकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्र की समस्याओं और जनता से जुड़े मुद्दों को संगठन तथा सरकार के सामने उठाना चाहिए,उनके मुताबिक संगठन केवल पदाधिकारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की सक्रियता से ही प्रभावी होता है, ताम्रध्वज साहू के इसी विषय पर प्रशिक्षण देने की पुष्टि अन्य रिपोर्टों में भी हुई है।

जल-जंगल-जमीन और पेसा कानून पर राजेश तिवारी का फोकस

एआईसीसी सचिव राजेश तिवारी ने आदिवासी समुदाय के विकास और कांग्रेस की भूमिका से जुड़े विषयों पर प्रशिक्षण दिया,उन्होंने आदिवासी समाज के जल, जंगल और जमीन से जुड़े संघर्ष तथा अधिकारों पर विस्तार से चर्चा की,प्रशिक्षण में पेसा कानून के प्रावधानों को भी प्रमुखता से रखा गया। आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन और ग्रामसभा की भूमिका से जुड़े प्रावधानों की जानकारी प्रशिक्षणार्थियों को दी गई,सरगुजा संभाग में आदिवासी आबादी और वन क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का हिस्सा रहे हैं, ऐसे में प्रशिक्षण के दौरान इन विषयों को संगठनात्मक स्तर पर कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने पर जोर दिया गया।

धर्म और धर्मनिरपेक्षता पर भूपेश बघेल का सत्र

दूसरे दिन के प्रमुख सत्रों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने'राजनीति में धर्म के उपयोग और धर्मनिरपेक्षता'विषय पर प्रशिक्षणार्थियों से संवाद किया,अपने संबोधन में बघेल ने भाजपा की राजनीति और धर्म के उपयोग को लेकर आलोचनात्मक राजनीतिक टिप्पणी की,उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अपनी सरकार की विफलताओं को छिपाने के लिए धार्मिक मुद्दों के जरिए सामाजिक विभाजन पैदा करने का प्रयास करती है, उन्होंने कहा कि अब सरकार की विफलताओं और जनसमस्याओं पर खुलकर चर्चा हो रही है, यह राजनीतिक आरोप पूर्व मुख्यमंत्री बघेल की ओर से व्यक्त किया गया दृष्टिकोण है,प्रशिक्षण में धर्म और धर्मनिरपेक्षता के राजनीतिक प्रभावों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पार्टी के नजरिए से जानकारी दी गई,अन्य स्रोतों ने भी दूसरे दिन बघेल के धर्म और धर्मनिरपेक्षता विषयक सत्र की पुष्टि की है।

दीपक बैज ने बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर दिया जोर-दूसरे दिन के अंतिम प्रमुख सत्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने संगठन निर्माण,संगठन की जिम्मेदारियों और उसके महत्व पर प्रशिक्षण दिया,उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया,ब्लॉक अध्यक्षों और मास्टर ट्रेनरों को यह जिम्मेदारी दी जा रही है कि प्रशिक्षण में प्राप्त जानकारी को आगे मंडल और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरगुजा में आयोजित यह शिविर कांग्रेस के संभागवार प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा है। इससे पहले बस्तर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में भी इस तरह के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा चुके हैं,सरगुजा शिविर में कुल 12 सत्रों के माध्यम से संगठनात्मक प्रशिक्षण की रूपरेखा तैयार की गई है।

संचार और सोशल मीडिया को भी प्रशिक्षण का हिस्सा बनाया-शिविर में बदलते राजनीतिक और सामाजिक संचार के दौर को देखते हुए संचार और सोशल मीडिया को भी प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया,कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने संचार व्यवस्था और 'संचार सदनों' के उपयोग से जुड़े विषयों पर जानकारी दी,उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका को लेकर पार्टी के दृष्टिकोण पर भी बात रखी तथा'छद्म राष्ट्रभक्ति' जैसे राजनीतिक विमर्श से जुड़े मुद्दे उठाए,वहीं सोशल मीडिया के सत्र में मणि वैष्णव ने डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका और सोशल मीडिया के माध्यम से संगठनात्मक गतिविधियों को लोगों तक पहुंचाने के तौर-तरीकों पर जानकारी दी।

दीपक मिश्रा ने ऑनलाइन व्यवस्थाओं तथा कांग्रेस के 'कनेक्ट कांग्रेस' से जुड़े प्रक्रियात्मक विषयों की जानकारी दी,दूसरे दिन के प्रशिक्षण में संगठन के पारंपरिक ढांचे के साथ डिजिटल संचार को जोड़ने पर भी विशेष ध्यान दिखाई दिया,अन्य रिपोर्टों में भी शिविर के दौरान सोशल मीडिया और ऑनलाइन संगठनात्मक व्यवस्था से जुड़े सत्र आयोजित किए जाने की पुष्टि हुई है।

अंतिम दिन चरणदास महंत छात्रों और पेपर लीक के मुद्दे पर करेंगे संबोधन-तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का अंतिम दिन 17 सितंबर को आयोजित होगा,अंतिम दिन नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करेंगे,प्रस्तावित सत्र में पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। महंत के अंबिकापुर पहुंचने की जानकारी भी दी गई है, प्रशिक्षण के समापन अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों और मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण पूर्ण करने के प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे।

मास्टर ट्रेनरों के जरिए बूथ तक पहुंचेगा प्रशिक्षण-कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत आयोजित इस प्रशिक्षण की अगली कड़ी इसे बूथ स्तर तक ले जाना है। प्रशिक्षण में शामिल मास्टर ट्रेनर आगे मंडल और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक गतिविधियों,जनसंपर्क और पार्टी के कार्यक्रमों से जुड़े विषयों पर प्रशिक्षण देंगे, प्रभारी महामंत्री संगठन मलकीत गैदू ने कहा कि प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणपत्र दिए जाएंगे और उम्मीद है कि प्रशिक्षण की यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी, उनका जोर इस बात पर रहा कि प्रशिक्षण के माध्यम से संगठनात्मक गतिविधियां केवल ब्लॉक स्तर तक सीमित न रहें, बल्कि बूथ स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचें।

12 सत्रों में संगठन को जमीनी स्तर तक ले जाने की कवायद

सरगुजा संभाग के छह जिलों के 49 ब्लॉक अध्यक्षों और 12 मास्टर ट्रेनरों को शामिल कर आयोजित यह शिविर कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की संभागीय कड़ी है, तीन दिनों में कुल 12 सत्रों की योजना है, जिनमें संगठन, राजनीतिक विषय, जनसंपर्क,संचार,सोशल मीडिया और जमीनी स्तर की गतिविधियों से जुड़े अलग-अलग पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, दूसरे दिन सात सत्रों के दौरान वरिष्ठ नेताओं और प्रशिक्षकों ने अलग-अलग विषयों पर अपनी बात रखी,अब अंतिम दिन होने वाले सत्रों के साथ शिविर का औपचारिक समापन होगा और प्रशिक्षित ब्लॉक अध्यक्षों तथा मास्टर ट्रेनरों की जिम्मेदारी अपने-अपने क्षेत्रों में संगठनात्मक प्रशिक्षण को आगे बढ़ाने की होगी।

छात्रा की आत्महत्या मामले की एफआईआर में नाम आया,एमए छात्र का प्रवेश निरस्त

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की कार्रवाई

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,16 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर ने एमए इतिहास प्रथम सेमेस्टर के छात्र ज्ञान तिवारी का प्रवेश निरस्त कर दिया है। कॉलेज प्रबंधन के अनुसार, छात्र का नाम महाविद्यालय की एक छात्रा की आत्म हत्या के मामले में दर्ज एफआईआर में शामिल है। इस मामले में जारी कारण बताओ नोटिस का निर्धारित समय में जवाब नहीं देने पर कॉलेज की अनुशासन समिति एवं एंटी रैगिंग समिति के निर्णय के आधार पर कार्रवाई की गई है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अनिल कुमार सिन्हा ने 16 सितंबर को जारी आदेश में बताया कि छात्र को 11 सितंबर को आठ बिंदुओं से संबंधित कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। निर्धारित समय सीमा में छात्र ने अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया। छात्रा अंतरा साह बीए प्रथम सेमेस्टर द्वारा 12 सितंबर को की गई आत्महत्या के प्रकरण में दर्ज एफआईआर में ज्ञान तिवारी का नाम शामिल होने के आधार पर यह कार्रवाई की गई।

फ्रेशर कार्यक्रम को लेकर भी विवाद : महाविद्यालय परिसर में 7 सितंबर को आयोजित फ्रेशर कार्यक्रम को लेकर भी विवाद सामने आया था। कॉलेज प्रबंधन के अनुसार, ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में ज्ञान तिवारी की भूमिका को लेकर आपत्तियां सामने आई थीं। इसके बाद छात्र के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई। आत्महत्या प्रकरण में एफआईआर में नाम आने के बाद मामले को लेकर कॉलेज में असंतोष का माहौल भी बना हुआ था।

प्रताड़ना से तंग आकर छात्रा ने की थी आत्महत्या : 12 सितंबर को छात्रा अंतरा साह ने अपने जीजा के घर पटपरिया में आत्महत्या कर ली थी। मामले में गांधीनगर पुलिस ने आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले में आरोपी ज्ञान तिवारी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। ज्ञान तिवारी एनएसयूआई नेता है। कांग्रेस ने भी आरोपी ज्ञान तिवारी के खिलाफ संगठनात्मक कार्रवाई करते हुए कांग्रेस की सदस्याता रद्द कर दी है।

दामाद ने ससुर की हत्या की दी सुपारी,झारखंड से बुलाए तीन बदमाश

रसूलपुर में 70 वर्षीय बुजुर्ग की चाकू से गोदकर हत्या...सीसीटीवी से खुला राज...दामाद समेत दो हिरासत में...अन्य आरोपियों की तलाश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,16 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

शहर के रसूलपुर मोहल्ले में बुधवार सुबह 70 वर्षीय बशीरुद्दीन सिद्दीकी उर्फ लज्जू की हत्या की वारदात ने सनसनी फैला दी। घर के बाहर कमरे में बैठे बुजुर्ग पर बाइक से पहुंचे तीन बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। वारदात के बाद आरोपी बाइक छोड़कर पैदल फरार हो गए। गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती बुजुर्ग की दोपहर इलाज के दौरान मौत हो गई। वारदात की जांच में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से अहम सुराग मिले। पुलिस के अनुसार, मृतक के दामाद नाजीम ने ही ससुर की हत्या की साजिश रची थी और झारखंड के चैनपुर व पांकी थाना क्षेत्र से तीन बदमाशों को सुपारी देकर बुलाया था। पुलिस ने दामाद समेत दो आरोपियों को हिरासत में लिया है,जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बशीरुद्दीन

बुधवार सुबह करीब 10 बजे अपने घर के बाहर बने कमरे में बैठे थे। परिवार के अन्य सदस्य अंदर थे। इसी दौरान बाइक से तीन युवक पहुंचे और कमरे में जाकर उनसे बातचीत करने लगे। कुछ देर बाद एक युवक ने चाकू निकाला और बशीरुद्दीन के पेट में लगातार तीन वार कर दिए। बुजुर्ग ने बचने के लिए संघर्ष करते हुए शोर मचाया। आवाज सुनकर परिजन बाहर आए तो तीनों आरोपी कमरे से निकलकर बाइक वहीं छोड़कर पैदल भाग गए। परिजन पड़ोसियों की मदद से घायल बशीरुद्दीन को मिशन अस्पताल ले गए। पुलिस केस होने के कारण वहां इलाज नहीं हो सका। इसके बाद उन्हें फिरदौसी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

सीसीटीवी फुटेज से मिला अहम सुराग : शहर के बीचोंबीच हुई हत्या की सूचना मिलते ही आईजी दीपक झा, एसएसपी राजेश अग्रवाल,सीएसपी राहुल बंसल समेत पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल की जांच के साथ आरोपियों की तलाश के लिए शहर और जिले में नाकेबंदी कराई। मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच के दौरान तीनों आरोपी वारदात के बाद भागते हुए दिखाई दिए। फुटेज और परिजनों से पूछताछ के आधार पर पुलिस को मृतक के दामाद पर संदेह हुआ। इसके बाद पुलिस ने उसे तकिया मजार स्थित उसके घर से हिरासत में लिया। उसकी निशानदेही पर एक अन्य आरोपी को भी पकड़ा गया है।

बेटी से तलाक का मामला कोर्ट में : पुलिस के अनुसार,नाजीम मूलतः झारखंड के चैनपुर का रहने वाला है और अंबिकापुर के तकिया क्षेत्र में भी उसका घर है। मृतक की बेटी और नाजीम के बीच तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। बेटी फिलहाल मायके में रह रही है। पुलिस का कहना है कि इसी विवाद के चलते नाजीम ने ससुर की हत्या की साजिश रची और झारखंड से तीन बदमाशों को बुलाया।

मजदूरों ने पिस्टल देखने की बात कही : घटनास्थल के पास काम कर रहे कुछ मजदूरों ने बदमाशों के हाथ में पिस्टल होने की बात कही है। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद ही हथियारों के संबंध में स्थिति स्पष्ट होगी।

19 सितंबर को गणपति धाम हाथीपखना में होगी भव्य महाआरती

कलेक्टर-एसपी सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने लिया तैयारियों का जायजा,सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा पर चर्चा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,16 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

गणपति धाम हाथीपखना में 19 सितंबर को आयोजित होने वाली भव्य महाआरती की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का जायजा लेने बुधवार को कलेक्टर अजीत वसंत,पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल,डीएफओ लोकनाथ पटेल,निगम आयुक्त विनय अग्रवाल सहित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया।

अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल पर श्रद्धालुओं के आवागमन,सुरक्षा,यातायात,पार्किंग, भीड़ नियंत्रण एवं दर्शन व्यवस्था को लेकर चर्चा की। महाआरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए। इस दौरान एसडीएम,अपर कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बाल गंगाधर तिलक गणपति कार्यकर्ताओं में जनमेजय मिश्रा,अनीश सिंह,अविनाश मंडल,रवि विश्वकर्मा सहित ट्रस्ट के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ट्रस्ट अध्यक्ष शैलेश सिंह 'शैलू' ने बताया कि 19 सितंबर को गणपति धाम हाथीपखना में महाआरती का भव्य आयोजन किया जा रहा है।

नवोदय की 9 वीं-11वीं की रिक्त सीटों के लिए 30 तक आवेदन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,16 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

जवाहर नवोदय विद्यालय समिति ने सत्र 2027-28 में कक्षा 9 वीं एवं 11वीं की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए लेटरल एंट्री सेलेक्शन टेस्ट (एलईएसटी 2027) के ऑनलाइन आवेदन शुरू किए हैं। पात्र विद्यार्थी 30 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर ने जिले के सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों तथा शासकीय,अशासकीय, अनुदान प्राप्त एवं निजी विद्यालयों के प्राचार्यों और प्रबंधकों को इसकी जानकारी विद्यार्थियों एवं अभिभावकों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। कक्षा 8वीं एवं 10वीं में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

CMYK

अध्यक्ष पद की दौड़ तेज...संजय ने कार्ड से गिनाईं उपलब्धियां,प्रशांत ने घर-घर बांटे दीपक

बैकुंठपुर में दावेदारों ने शुरू किया जनसंपर्क का अलग-अलग अंदाज,काम और संकल्प के साथ जनता तक पहुंचने की कोशिश

-रवि सिंह-

बैकुंठपुर/कोरिया,16 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

दिसंबर 2026 में प्रस्तावित बैकुंठपुर नगर पालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल अब धीरे-धीरे दावेदारों के जनसंपर्क अभियान में बदलती दिखाई दे रही है,अध्यक्ष पद के संभावित दावेदार अब केवल पार्टी के भीतर अपनी दावेदारी रखने तक सीमित नहीं हैं,बल्कि अलग-अलग माध्यमों से जनता के बीच अपनी पहचान,उपलब्धियां,विचार और भविष्य की योजनाएं सामने रख रहे हैं।

इसी क्रम में तीन बार निर्वाचित पार्षद संजय जायसवाल ने अपने कार्यों,संघर्ष और नगर के लिए अपनी प्राथमिकताओं को सामने रखने वाला कार्ड वितरित कराया है,वहीं सीए प्रशांत गुप्ता की ओर से घर-घर दीपक पहुंचाने की पहल भी चर्चा में है,दोनों गतिविधियों का स्वरूप अलग है,लेकिन राजनीतिक संदेश एक ही है– अध्यक्ष पद की दौड़ में दावेदार अब जनता के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराने लगे हैं,हालिया स्थानीय रिपोर्टों में भी संजय जायसवाल की नगर पालिका से जुड़े मुद्दों पर लगातार सक्रियता का उल्लेख हुआ है, उन्होंने सामान्य सभा से पहले पेट्रोल-डीजल भुगतान और जलापूर्ति योजना सहित विभिन्न विषयों पर जांच एवं कार्रवाई की मांग उठाई थी।

संजय जायसवाल का कार्ड....संघर्ष से सेवा तक का संदेश-संजय जायसवाल द्वारा वितरित कराए गए कार्ड में उनकी राजनीतिक और सामाजिक यात्रा के साथ-साथ नगर के विकास को लेकर उनके विचारों को प्रमुखता दी गई है,कार्ड में उन्हें तीन बार निर्वाचित पार्षद और समाजसेवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, कार्ड में नगर की राजनीति में उनके संघर्ष,जनता के मुद्दों को उठाने और विभिन्न मामलों में आंदोलन किए जाने का उल्लेख है। साथ ही अध्यक्ष बनने की स्थिति में जनता के साथ बैठक कर शहर के लिए 100 दिनों का रोडमैप तैयार करने की बात कही गई है,उनके संदेश में यह भी कहा गया है कि अध्यक्ष का कार्यालय केवल कार्यालय तक सीमित नहीं रहना चाहिए,बल्कि व्यवस्था को जनता के बीच पहुंचना चाहिए,कार्ड में प्रेसिडेंट-इन-काउंसिल की बैठक, नगर पालिका परिषद की बैठक और प्रत्येक सप्ताह जनदर्शन जैसे प्रस्तावों का उल्लेख किया गया है,इस तरह संजय जायसवाल ने अपनी दावेदारी को केवल व्यक्तिगत राजनीतिक इच्छा के रूप में नहीं, बल्कि नगर पालिका की कार्यप्रणाली और जनभागीदारी से जोड़कर जनता के सामने रखने का प्रयास किया है।

एक तरफ अनुभव,दूसरी तरफ नई पीढ़ी का दावा-संजय जायसवाल की प्रचार सामग्री में लंबे समय के पार्षदीय अनुभव और मुद्दों पर संघर्ष को आधार बनाया गया है,वहीं प्रशांत गुप्ता जैसे युवा दावेदारों की गतिविधियों में नई शैली और नए तरीके से जनता तक पहुंचने की कोशिश दिखाई दे रही है,यहीं से बैकुंठपुर चुनाव की एक महत्वपूर्ण तस्वीर उभरती है...क्या अध्यक्ष पद के लिए दावेदार अपनी पुरानी राजनीतिक सक्रियता और अनुभव के आधार पर जनता के बीच जाएंगे या नई सोच, नई कार्यशैली और नए जनसंपर्क मॉडल को सामने रखेंगे? हालांकि अंतिम रूप से टिकट किसे मिलेगा,यह संबंधित राजनीतिक दल के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगा। अभी दावेदारों की गतिविधियां मुख्यतः अपनी दावेदारी को जनता और संगठन दोनों के सामने मजबूत करने की दिशा में दिखाई दे रही हैं।

कार्ड में लिखे वादे बनाम जमीन पर सवाल-चुनावी मौसम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि प्रचार सामग्री में दर्ज वादे और प्राथमिकताएं जनता के सामने कितनी प्रभावी ढंग से रखी जाती हैं। सड़क,पानी, नाली,स्ट्रीटलाइट,स्वच्छता,पार्किंग,बाजार व्यवस्था और रोजगार जैसे स्थानीय मुद्दे सीधे नगरवासियों के रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हैं, इसलिए आने वाले दिनों में दावेदारों के बीच मुकाबला केवल 'कौन कितना प्रचार कर रहा है' तक सीमित नहीं रहेगा,जनता के बीच यह सवाल भी उठेगा कि कौन दावेदार नगर की समस्याओं को कितनी स्पष्टता से समझता है और उनके समाधान की क्या कार्ययोजना सामने रखता है।

भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ संघर्ष को बनाया आधार

संजय जायसवाल के प्रचार सामग्री में नगर पालिका और अन्य विभागों से जुड़े कथित भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के खिलाफ उनके द्वारा उठाई गई आवाज को भी प्रमुख स्थान दिया गया है, कार्ड में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक मामले,दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद संबंधित अधिकारी के स्थानांतरण तथा बाद की न्यायिक कार्रवाई को उनके संघर्ष का हिस्सा बताया गया है,इसके अलावा नगर की सड़क,नाली,जल व्यवस्था,स्ट्रीट लाइट,आवास और अन्य नागरिक सुविधाओं को लेकर उनकी प्राथमिकताएं भी दर्ज हैं,हालिया रिपोर्टों के अनुसार भी जायसवाल ने नगर पालिका में डीजल-पेट्रोल भुगतान तथा जलापूर्ति पाइपलाइन कार्य को लेकर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है। ये उनके मौजूदा सार्वजनिक मुद्दों पर फोकस को दर्शाते हैं।

सीए प्रशांत गुप्ता ने दीपक के जरिए घर-घर पहुंचाया संदेश

दूसरी ओर अध्यक्ष पद के युवा दावेदारों में चर्चा में चल रहे सीए प्रशांत गुप्ता की ओर से घर-घर दीपक पहुंचाने की पहल सामने आई है, उनके प्रचार कार्ड में 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम से जुड़े संदेश के साथ दीपक वितरण को जोड़ा गया है,यह पहल ऐसे समय सामने आई है जब भाजपा के भीतर बैकुंठपुर अध्यक्ष पद के लिए कई नाम चर्चा में हैं,प्रशांत गुप्ता के इस जनसंपर्क का तरीका पारंपरिक राजनीतिक प्रचार से कुछ अलग दिखाई देता है,घर-घर पहुंचकर दीपक देना सीधे परिवारों तक संपर्क बनाने का माध्यम बन रहा है, यानी एक ओर संजय जायसवाल अपने काम,संघर्ष और भविष्य के रोडमैप को जनता के सामने रख रहे हैं,तो दूसरी ओर प्रशांत गुप्ता सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम और व्यक्तिगत जनसंपर्क के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं।

सरगुजा संभाग में 44 सड़कों के लिए 1093 करोड़ स्वीकृत

-संवाददाता-

अंबिकापुर,16 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा संभाग के छह जिलों में सडक़ नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 44 प्रमुख सडक़ परियोजनाओं को 1093.73 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। लोक निर्माण विभाग द्वारा सरगुजा,सूरजपुर,बलरामपुर-रामानुजगंज, जशपुर,कोरिया और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिलों में नई सडक़ों के निर्माण के साथ चौड़ीकरण, डामरीकरण, सुदृढ़ीकरण और पुल-पुलिया निर्माण के कार्य कराए जाएंगे।

सरगुजा जिले में लरंगसाय चौक से रामानुजगंज मार्ग के 5 किमी फोरलेन के लिए 69.10 करोड़ तथा गांधी चौक से रेलवे स्टेशन तक 5 किमी फोरलेन के लिए 61.34 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सीतापुर क्षेत्र में सोनतराई से सूर तक 4 किमी फोरलेन निर्माण के लिए 34.22 करोड़ रुपए मिलेंगे।

सूरजपुर जिले में तारा-प्रेमनगर-रामानुजनगर-कृष्णपुर मार्ग के 63 किमी सुदृढ़ीकरण के लिए 64.93 करोड़ रुपए सहित कई प्रमुख मार्गों के लिए राशि स्वीकृत हुई है। बलरामपुर-रामानुजगंज में परसवार-चलगली मार्ग के उन्नयन के लिए 38.80 करोड़ रुपए स्वीकृत हैं। जशपुर में लुड़ेग-बागबहार-तपकरा-लवाकेरा राज्य मार्ग के 55.80 किमी सुदृढ़ीकरण के लिए 40.32 करोड़ रुपए मिलेंगे। परियोजनाओं से ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और रोजगार तक पहुंच आसान होने की उम्मीद है।

पीजी कॉलेज छात्रा आत्महत्या मामला: निष्पक्ष जांच की मांग,पुलिस महानिरीक्षक को सौंपा पत्र

जिला पंचायत सदस्य आदित्येश्वर शरण सिंह देव ने कहा...जांच से सामने आए आत्महत्या के कारण,दोषी पाए जाने वाले पर हो कड़ी कार्रवाई

-संवाददाता-

अंबिकापुर,16 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

शासकीय राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्रा की आत्महत्या के मामले में निष्पक्ष और तेज जांच की मांग उठी है। जिला पंचायत सदस्य आदित्येश्वर शरण सिंह देव ने 16 सितंबर को पुलिस महा निरीक्षक,सरगुजा रेंज के नाम पत्र सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने का आग्रह किया है,पत्र में कहा गया है कि जांच के माध्यम से आत्महत्या के वास्तविक कारण सामने आने चाहिए और यदि किसी व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

परिजनों ने छात्र नेता पर प्रताड़ना का लगाया आरोप-पुलिस महानिरीक्षक को दिए गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि पीजी कॉलेज की एक छात्रा की आत्महत्या का मामला सामने आने के बाद परिजनों ने एनएसयूआई के छात्र नेता ज्ञान तिवारी पर छात्रा को लगातार परेशान करने का आरोप लगाया था, परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और मोबाइल फोन भी जब्त किए, पत्र में कहा गया है कि आरोप और जांच की कार्रवाई के बीच छत्र नेता ज्ञान तिवारी को गिरफ्तार किया गया है, हालांकि छात्रा की आत्महत्या के पीछे वास्तविक कारण क्या था और आरोपों में कितनी सच्चाई है, यह जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट होना बाकी है,मामले में पुलिस की कार्रवाई के संबंध में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार ज्ञान तिवारी को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने छात्रा और आरोपी के मोबाइल जब्त कर तकनीकी साक्ष्यों की जांच शुरू की है।

परिजनों की मांग—हर पहलू की हो जांच- जिला पंचायत सदस्य ने अपने पत्र में कहा है कि छात्रा के परिजनों ने उनसे मुलाकात कर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग रखी है, इसी के आधार पर उन्होंने पुलिस महानिरीक्षक से मामले की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया है,पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि जांच केवल लगाए गए आरोपों तक सीमित न रहे,बल्कि आत्महत्या से जुड़े सभी संभावित पहलुओं की पड़ताल की जाए। इससे यह स्पष्ट हो सके कि छात्रा ने इतना बड़ा कदम किन परिस्थितियों में उठाया।

तकनीकी साक्ष्य भी जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा-मामले में पुलिस द्वारा मोबाइल फोन जब्त किए जाने की जानकारी सामने आई है,प्रकाशित रिपोर्टों के मुताबिक छात्रा और आरोपी के मोबाइल से कुछ चैट डिलीट होने की बात सामने आई है और पुलिस तकनीकी माध्यमों से इन्हें रिकवर करने का प्रयास कर रही है,ऐसे में डिजिटल साक्ष्य, मोबाइल डेटा और संबंधित व्यक्तियों के बयान जांच की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

राजनीतिक और छात्र संगठनों की गतिविधियां भी सामने आईं...

छात्रा की मौत के बाद मामले ने छात्र राजनीति का रूप भी ले लिया था,एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने गांधीनगर थाने के बाहर प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की थी। वहीं कांग्रेस की ओर से भी आरोपी छात्र नेता के खिलाफ संगठनात्मक कार्रवाई की जानकारी सामने आई है,इस बीच पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भी मामले में निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

अब जांच की निष्पक्षता पर नजर

पुलिस के सामने अब छात्रा की आत्महत्या से जुड़े घटनाक्रम,परिजनों और सहेलियों के बयान,मोबाइल व डिजिटल साक्ष्य तथा आरोपी से संबंधित सभी तथ्यों की जांच की चुनौती है,जिला पंचायत सदस्य द्वारा पुलिस महानिरीक्षक को दिए गए पत्र में भी इसी बिंदु पर जोर दिया गया है कि जांच निष्पक्ष और गंभीरता से हो,ताकि मामले की वास्तविकता सामने आ सके और यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई हो।

एनएच-343 पर ऑडियो बवाल...कंपनी ने पूर्व लेखापाल पर लगाया दो लाख की उगाही का आरोप,पुलिस चौकी पहुंचा मामला

-संवाददाता-

रामानुजगंज,16 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

रामानुजगंज से बलरामपुर तक बन रहे एनएच-343 सड़क प्रोजेक्ट को लेकर विवाद अब पुलिस चौकी तक पहुंच गया है। जानकारों की मानें तो शिवालिक बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विनोद लाम्बा ने तातापानी पुलिस चौकी में आवेदन देकर कंपनी के पूर्व लेखापाल सर्वेश शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कंपनी का आरोप है कि पूर्व कर्मचारी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर कंपनी को बदनाम करने के उद्देश्य से भ्रामक ऑडियो तैयार कराया और उसे प्रसारित एवं प्रकाशित कराया। शिकायत में कथित रूप से दो लाख रुपये की उगाही का आरोप भी लगाया गया है।

पूर्व कर्मचारी पर डेटा नहीं लौटाने का आरोप : कंपनी के आवेदन के अनुसार, सर्वेश शर्मा को दिसंबर 2025 में लेखापाल के पद पर नियुक्त किया गया था। वह 30 अप्रैल 2026 तक कंपनी का लेखा संबंधी काम देख रहा था। कंपनी का कहना है कि उसके कार्य से कंपनी को नुकसान हो रहा था,जिसके आधार पर उसे पद से अलग कर दिया गया। शिकायत में आरोप है कि पद से हटाए जाने के बाद कंपनी का पूरा डेटा वापस नहीं किया गया। इसके बाद पूर्व कर्मचारी पर कुछ लोगों के साथ मिलकर कंपनी की छवि खराब करने के उद्देश्य से ऑडियो तैयार कराने का आरोप लगाया गया है। कंपनी ने दावा किया है कि वायरल ऑडियो में सुनाई देने वाली आवाज सर्वेश शर्मा की है। हालांकि,आवाज की स्वतंत्र पुष्टि अभी सामने नहीं आई है।

ऑडियो और कैश-बुक के सवाल भी बरकरार : एनएच-343 को लेकर इससे पहले सामने आई मीडिया रिपोर्टों में सड़क की गुणवत्ता, कथित कैश-बुक और वायरल ऑडियो को लेकर सवाल उठाए गए थे। एक रिपोर्ट में 11 लाख 39 हजार रुपये की कथित कैश-बुक का उल्लेख किया गया था। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

अब कंपनी की शिकायत के बाद मामला और गंभीर हो गया है। यदि ऑडियो भ्रामक है तो इसकी तकनीकी जांच होनी चाहिए। वहीं,यदि ऑडियो में सड़क निर्माण या भुगतान से जुड़े आरोप हैं,तो उनकी भी अलग से जांच जरूरी है। कंपनी की शिकायत से सड़क निर्माण की गुणवत्ता से जुड़े मूल सवाल खत्म नहीं हो जाते।

मानहानि की धाराओं में कार्रवाई की मांग : विनोद लाम्बा ने 16 सितंबर को तातापानी पुलिस चौकी में आवेदन देकर भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(1) एवं 356(3) के तहत कार्रवाई की मांग की है। शिकायत की प्रतियां कलेक्टर बलरामपुर, पुलिस अधीक्षक बलरामपुर-रामानुजगंज और थाना प्रभारी रामानुजगंज को भी दिए जाने की बात कही गई है। फिलहाल उपलब्ध दस्तावेज में एफआईआर दर्ज होने या आरोपों की जांच के परिणाम की जानकारी नहीं है। ऐसे में पूर्व लेखापाल पर लगाए गए आरोपों को शिकायतकर्ता का पक्ष माना जाना चाहिए, अपराध सिद्ध होने का निष्कर्ष नहीं।

सड़क की गुणवत्ता पर भी हो निष्पक्ष जांच : एनएच-343 क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़क परियोजना है। सड़क निर्माण में गुणवत्ता,

सामग्री, भुगतान और तकनीकी निगरानी से जुड़े सवालों का जवाब विभागीय रिकॉर्ड और तकनीकी जांच से मिलना चाहिए। प्रशासन को चाहिए कि वायरल ऑडियो,कथित कैश-बुक और सड़क निर्माण की गुणवत्ता–तीनों की स्वतंत्र जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करे।

पुल टूटा डेढ़ साल से,रपटा भी बह गया...अब सड़क चौड़ीकरण का भूमिपूजन!

गोबरी नदी में पुल का इंतजार,डुमरिया-केवड़ा सड़क चौड़ीकरण का भूमिपूजन...

डुमरिया-केवड़ा मार्ग पर विकास की प्राथमिकता पर सवाल...गोबरी नदी के स्थायी पुल का इंतजार जारी...

पुल अधूरा,रपटा बहा... करोड़ों की सड़क का भूमिपूजन...

पहले पुल संभालते तो बात बनती,अब करोड़ों की सड़क का भूमिपूजन...

गोबरी नदी का पुल सवालों में,डुमरिया-केवड़ा सड़क का भूमिपूजन चर्चा में...

सड़क चौड़ी होगी,गोबरी नदी कैसे पार होगी? पुल टूटने के डेढ़ साल बाद बड़ा सवाल...

करोड़ों की सड़क,नदी पर टूटा पुल–डुमरिया-केवड़ा विकास मॉडल पर सवाल...

पुल टूटा,रपटा बहा...फिर भी सड़क चौड़ीकरण का भूमिपूजन...

गोबरी नदी का पुल अब भी इंतजार में, डुमरिया-केवड़ा सड़क को मिली नई शुरुआत

15 लाख का रपटा नहीं टिका,अब करोड़ों की सड़क पर निगाहें...पुल कब बनेगा?

डुमरिया-केवड़ा मार्ग पर विकास की प्राथमिकता पर सवाल,गोबरी नदी के स्थायी पुल का इंतजार जारी

दैनिक घटती-घटना की पिछली खबर का बड़ा अपडेट : सड़क चौड़ीकरण शुरू होने से पहले ही सामने आई सबसे बड़ी चुनौती,करोड़ों की सड़क किस काम की जब नदी पर रास्ता ही अधूरा?

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर/भैयाथान,16 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। डुमरिया से केवड़ा पहुंच मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर आखिरकार भूमिपूजन हो गया है,करोड़ों रुपये की इस सड़क परियोजना को क्षेत्र के आवागमन और विकास से जोड़कर देखा जा रहा है,लेकिन इस पूरे विकास कार्य के बीच एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है, जिसका जवाब सड़क का भूमिपूजन भी नहीं दे पा रहा है, सवाल है की डुमरिया-केवड़ा मार्ग की शुरुआत में ही गोबरी नदी पर करीब डेढ़ साल से टूटा पड़ा पुल आखिर कब बनेगा? जिस मार्ग को चौड़ा करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जाने हैं, उसी मार्ग पर गोबरी नदी ग्रामीणों के आवागमन की सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। पुराना पुल टूटने के बाद ग्रामीणों की परेशानी कम करने के लिए करीब 15 लाख की लागत से अस्थायी रपटा बनाया गया, लेकिन वह भी बारिश की मार नहीं झेल सका और बह गया, इसके बाद भी स्थायी समाधान को लेकर ग्रामीणों की प्रतीक्षा खत्म नहीं हुई है,अब सड़क चौड़ीकरण का भूमिपूजन हो चुका है। ऐसे में दैनिक घटती घटना की पूर्व खबर का यह सीधा अपडेट है कि सड़क के विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है,लेकिन उसी सड़क की सबसे जरूरी कड़ी गोबरी नदी का स्थायी पुल अभी भी सवालों के घेरे में है।

पहले टूटा पुल,फिर बना रपटा,अब रपटा भी नहीं...

गोबरी नदी पर पुल टूटने के बाद ग्रामीणों के सामने आवागमन का संकट खड़ा हुआ था, उस समय तत्काल राहत के लिए अस्थायी रपटा तैयार करने की कवायद शुरू हुई, ग्रामीणों को उम्मीद थी कि कम से कम अस्थायी रास्ते से आवागमन की समस्या कुछ समय के लिए दूर हो जाएगी और इसी बीच स्थायी पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा, लेकिन अस्थायी व्यवस्था भी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी, करीब 15 लाख की लागत से बनाया गया रपटा बारिश के पानी में बह गया, इससे यह सवाल और गंभीर हो गया कि आखिर अस्थायी व्यवस्था के नाम पर खर्च होने वाले लाखों रुपये का अपेक्षित लाभ ग्रामीणों को क्यों नहीं मिल पाया रपटा बहने के बाद फिर वही समस्या सामने है–नदी और उसके पार जाने का सुरक्षित रास्ता।

भूमिपूजन की जगह को लेकर भी चर्चा

डुमरिया से केवरा जाने वाले मार्ग के चौड़ीकरण का भूमिपूजन मार्ग के बीच के हिस्से में किए जाने को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा रही,सामान्य तौर पर बड़े सड़क प्रोजेक्ट के भूमिपूजन को लेकर लोगों की नजर परियोजना के आरंभिक बिंदु,प्रमुख पुल, पहुंच मार्ग और अंतिम छोर पर रहती है, स्थानीय लोगों का कहना है कि कार्यक्रम स्थल को लेकर भी क्षेत्र में अलग-अलग चर्चाएं हुई,कुछ लोगों ने इसे स्थानीय राजनीतिक एवं सामाजिक प्रभाव से जोड़कर देखा,हालांकि इस संबंध में किसी पक्ष की ओर से आधिकारिक रूप से ऐसी कोई वजह सामने नहीं आई है,इसलिए इसे फिलहाल स्थानीय चर्चा और राजनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में ही देखा जाना चाहिए,लेकिन कार्यक्रम स्थल से कहीं अधिक महत्वपूर्ण सवाल सड़क की उपयोगिता का है।

15 महिना बाद भी सवाल वहीं खड़ा- पुल टूटने के बाद समय बीतता गया, दो बरसात आई, ग्रामीणों ने परेशानी झेली,अस्थायी रपटा बनाया गया,रपटा भी बह गया,लेकिन अब जब उसी मार्ग के चौड़ीकरण का भूमिपूजन हो गया है,तब सवाल यह है कि क्या स्थायी पुल को सड़क परियोजना के साथ प्राथमिकता मिलेगी या फिर ग्रामीणों को एक और अस्थायी व्यवस्था का इंतजार करना पड़ेगा? 15 महिना का समय किसी छोटी अवधि का नाम नहीं है, इस दौरान सड़क चौड़ीकरण की योजना आगे बढ़ सकती है,भूमिपूजन हो सकता है, टेंडर प्रक्रिया पूरी हो सकती है,लेकिन जिस पुल के बिना यह मार्ग बरसात में बाधित हो सकता है,उसका स्थायी समाधान अभी भी ग्रामीणों के लिए सबसे बड़ा प्रश्न बना हुआ है।

30.41 करोड़ का टेंडर, 25 करोड़ में काम मिलने की चर्चा-डुमरिया-केवड़ा मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर स्थानीय स्तर पर करीब 30.41 करोड़ के टेंडर की चर्चा है,वहीं यह भी कहा जा रहा है कि यह काम करीब 25 करोड़ में मिला है, यह पूरा आंकड़ा अब सड़क निर्माण की गुणवत्ता और निगरानी के सवाल से भी जुड़ रहा है,यदि अनुमानित राशि और वास्तविक कार्यादेश राशि के बीच इतना अंतर है,तो स्वाभाविक रूप से यह जानना जरूरी होगा कि निविदा किस प्रक्रिया के तहत हुई, किस दर पर कार्य स्वीकृत हुआ और निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग के पास क्या व्यवस्था है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है–इस सड़क परियोजना में गोबरी नदी का स्थायी पुल किस स्थिति में है? क्योंकि सड़क चौड़ीकरण का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब सड़क के साथ पुल और अन्य आवश्यक संरचनाएं भी उसी स्तर पर तैयार हों।

30 जून 2025 में टूटा था गोबरी नदी का पुल-गोबरी नदी पर बना पुराना पुल 30 जून 2025 को भारी बारिश के बाद गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था,उस समय जिला प्रशासन ने पुल का निरीक्षण कर सुरक्षा की दृष्टि से दोनों ओर बैरिकेडिंग कर आवागमन बंद कराया था,प्रशासन ने नए पुल के लिए प्राक्कलन तैयार करने और वैकल्पिक मार्ग तैयार करने के निर्देश भी दिए थे,मामले की जांच के लिए तहसीलदार भैयाथान की अध्यक्षता में टीम गठित किए जाने की जानकारी भी सामने आई थी,यानी पुल टूटने की घटना अचानक सामने आने के बाद प्रशासनिक स्तर पर तत्काल कार्रवाई की बात कही गई थी, लेकिन एक साल से अधिक समय बीतने के बाद भी ग्रामीणों का मुख्य सवाल यही है कि स्थायी पुल आखिर कब बनेगा?

सड़क चौड़ी होगी तो क्या नदी पार करना आसान होगा?-सड़क विकास का उद्देश्य केवल सड़क की चौड़ाई बढ़ाना नहीं होता। सड़क तभी पूरी तरह उपयोगी होती है जब उस पर आने वाले प्रमुख नदी-नाले,पुल-पुलिया, एप्रोच रोड और कनेक्टिविटी भी सुचारु हों, डुमरिया-केवरा मार्ग के मामले में स्थिति कुछ अलग दिखाई देती है,एक तरफ 30.41 करोड़ रुपये की सड़क परियोजना स्वीकृत,दूसरी तरफ गोबरी नदी का पुराना पुल जून 2025 में क्षतिग्रस्त,फिर 15 लाख के आसपास का अस्थायी रपटा,इसके बाद रपटा और एप्रोच रोड को लेकर भी समस्याएं, और अब सड़क चौड़ीकरण का भूमिपूजन,ऐसे में ग्रामीणों के बीच स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठ रहा है कि परियोजना की प्राथमिकता में सड़क और नदी के पुल को किस क्रम में पूरा किया जाएगा?

भूमिपूजन से आगे अब काम की निगरानी की जरूरत-सड़क का भूमिपूजन किसी भी विकास परियोजना की शुरुआत का प्रतीक हो सकता है,लेकिन ग्रामीणों के लिए असली परीक्षा उसके बाद शुरू होती है, डुमरिया-केवरा मार्ग पर लोगों की अपेक्षा अब यह है कि सड़क चौड़ीकरण के साथ-साथ गोबरी नदी का स्थायी पुल,एप्रोच रोड, पुल-पुलिया और पूरी सड़क परियोजना एक समन्वित योजना के तहत समयबद्ध तरीके से पूरी हो,साथ ही निर्माण की गुणवत्ता की नियमित निगरानी हो और कार्य की प्रगति सार्वजनिक की जाए,क्योंकि यदि सड़क चौड़ी हो गई, लेकिन गोबरी नदी पर स्थायी पुल नहीं बना,तो ग्रामीणों के लिए करोड़ों रुपये की सड़क परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा फिर भी अधूरा ही रहेगा।

भूमिपूजन सड़क के बीच में,सवाल पुल के बीच में-डुमरिया से केवड़ा जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण का भूमिपूजन हुआ, लेकिन भूमिपूजन स्थल को लेकर भी स्थानीय स्तर पर चर्चा शुरू हो गई है,सड़क की शुरुआत डुमरिया से होती है,लेकिन भूमिपूजन गांव के बीच में किया गया। न सड़क के शुरुआती बिंदु पर और न अंतिम छोर पर,इसको लेकर विरोधियों ने सवाल उठाए हैं। स्थानीय स्तर पर इसे वर्चस्व की लड़ाई से जोड़कर भी देखा जा रहा है, लेकिन राजनीतिक चर्चा से अलग यदि पूरे मामले को सड़क और जनता की जरूरत के नजरिए से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल फिर वही है...भूमिपूजन स्थल चाहे जहां हो, गोबरी नदी पर पुल कब बनेगा? जनता के लिए कार्यक्रम की जगह से ज्यादा महत्वपूर्ण वह रास्ता है, जिस पर उन्हें रोजाना चलना है।

सड़क चौड़ी होगी,लेकिन नदी पर क्या होगा?-डुमरिया-केवड़ा मार्ग चौड़ा होने के बाद निश्चित रूप से यातायात व्यवस्था में सुधार की उम्मीद की जा सकती है,लेकिन सड़क का एक हिस्सा चौड़ा कर देने मात्र से पूरा संपर्क मार्ग मजबूत नहीं हो जाता,सड़क की उपयोगिता उसके पूरे नेटवर्क पर निर्भर करती है, यदि एक जगह पुल टूट जाए तो पूरी सड़क की कनेक्टिविटी प्रभावित होती है,गोबरी नदी इसी मार्ग की ऐसी कड़ी है,जहां पुराना पुल पहले ही टूट चुका है,ऐसे में सवाल है कि क्या सड़क चौड़ीकरण के साथ पुल निर्माण को समान प्राथमिकता दी गई है? क्या सड़क निर्माण और पुल निर्माण की समयसीमा एक-दूसरे से जुड़ी है? क्या सड़क पूरी होने से पहले पुल भी तैयार होगा? या फिर सड़क तैयार होने के बाद भी ग्रामीणों को नदी के पास पहुंचकर वही पुरानी समस्या झेलनी पड़ेगी?

15 लाख के रपटा पर भी जवाबदेही जरूरी-दैनिक घटती-घटना द्वारा पहले उठाए गए सवालों में 15 लाख के रपटा का मुद्दा भी प्रमुख रहा है,जब स्थायी पुल नहीं था तो अस्थायी रपटा ग्रामीणों के लिए तत्काल राहत का माध्यम था। लेकिन यदि वह बारिश में बह गया,तो उसकी तकनीकी मजबूती, निर्माण की गुणवत्ता और डिजाइन पर सवाल उठना स्वाभाविक है,यहां किसी व्यक्ति या संस्था पर सीधे दोष लगाने के बजाय जिम्मेदार विभाग से दस्तावेजी जवाब अपेक्षित है,रपटा किसके तकनीकी परीक्षण के बाद बनाया गया? उसकी डिजाइन किसने तैयार की? निर्माण की निगरानी किस अधिकारी ने की? भुगतान से पहले गुणवत्ता का परीक्षण हुआ या नहीं? रपटा बहने के बाद क्या विभागीय जांच हुई? और यदि जांच हुई तो उसकी रिपोर्ट क्या है? सबसे अहम सवाल अब तक जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई हुई? स्थानीय स्तर पर यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल निर्माण की तकनीकी विफलता का मामला नहीं है, बल्कि जनता के पैसे और जनता की सुविधा से जुड़ा विषय है।

पूर्व खबर से वर्तमान तक नहीं बदली मूल समस्या-दैनिक घटती-घटना ने जब पहली बार गोबरी नदी के टूटे पुल का मुद्दा उठाया था,तब सवाल था कि ग्रामीणों को आखिर कब स्थायी रास्ता मिलेगा,उसके बाद अस्थायी रपटा आया, रपटा भी चला गया, अब सड़क चौड़ीकरण का भूमिपूजन सामने है,

घटती घटना | कोरिया सूरजपुर समाचार | अम्बिकापुर गुरूवार 20 अगस्त 2026 | 5

पुल टूटा, रपटा बहा और अब सवालों की बाढ़!

14 महीने बाद भी स्थायी पुल अधूरा, 15 लाख का रपटा भी 15 दिन में बहा

30 जून 2025 : ध्वस्त हुआ मुख्य पुल

18 जुलाई 2026 : बहा वैकल्पिक रपटा

स्थायी पुल बनेगा कब? इंतजार कब तक?

पहले पुल बहा,फिर रपटा बहा...अब बहस में कौन बचेगा-जनता या जिम्मेदारी?

पुल कागजों में,रपटा नदी में...जनता फिर सड़क की तलाश में!

50 से ज्यादा खबरों के बाद भी पुल अधूरा,रपटा भी बहा...जनता का सवाल-अब कब बनेगा रास्ता?

स्थायी पुल बनने तक वैकल्पिक व्यवस्था जरूरी

दैनिक घटती-घटना के सवालों की भी हुई पुष्टि?

अब राजनीति नहीं, समयबद्ध कार्रवाई चाहिए...

पहले पुल टूटा, फिर रपटा बहा!

अंतिम सवाल...पुल कब बनेगा?

लेकिन मूल समस्या अभी भी वही है की गोबरी नदी पर स्थायी और सुरक्षित पुल,यानी घटनाक्रम जरूर आगे बढ़ा है, लेकिन ग्रामीणों की सबसे बड़ी जरूरत का अंतिम समाधान अभी उनके सामने दिखाई नहीं दे रहा, यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है।

विकास के दो चेहरे-डुमरिया-केवड़ा मार्ग की मौजूदा स्थिति विकास के दो अलग-अलग चेहरों को सामने रखती है,एक तरफ–करोड़ों रुपये की सड़क परियोजना,चौड़ीकरण का भूमिपूजन और बड़े स्तर पर निर्माण की तैयारी,दूसरी तरफ–गोबरी नदी पर टूटा पुल, ?15 लाख का बह चुका रपटा और ग्रामीणों की आवागमन संबंधी परेशानी,यही विरोधाभास अब सवाल बनकर सामने आ रहा है,क्या विकास का मतलब केवल सड़क को चौड़ा करना है,या उस सड़क को पूरी तरह आवागमन योग्य बनाना भी उतना ही जरूरी है?

सड़क का भूमिपूजन हो गया, अब जनता काम देखना चाहती है-भूमिपूजन के बाद अब जनता की नजर निर्माण पर होगी, अब सवाल भाषणों का नहीं है,अब सवाल यह है कि सड़क का काम कब शुरू होगा? काम की गुणवत्ता कैसी होगी? निर्माण कितनी तेजी से होगा? 25 करोड़ में कार्य मिलने की बात की वास्तविक स्थिति क्या है? गोबरी नदी के स्थायी पुल का निर्माण कब शुरू होगा? पुल कब तक पूरा होगा? बारिश में ग्रामीणों के आवागमन की व्यवस्था क्या होगी? 15 लाख के रपटा के बहने के मामले में जवाबदेही किसकी तय होगी? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में इस परियोजना की वास्तविक तस्वीर सामने रखेंगे।

क्या सड़क से पहले पुल जरूरी नहीं था?-यह सवाल ग्रामीणों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में है,जब सड़क की शुरुआत में ही पुल नहीं है तो सड़क चौड़ीकरण की प्राथमिकता पर सवाल उठना स्वाभाविक है,सड़क के चौड़ीकरण का लाभ तभी मिलेगा,जब डुमरिया से केवड़ा तक आवागमन निर्बाध हो,यदि बीच में गोबरी नदी पर रास्ता बाधित है,तो चौड़ी सड़क भी अपनी पूरी उपयोगिता नहीं दे पाएगी, इसलिए अब ग्रामीण यह देखना चाहते हैं कि सड़क चौड़ीकरण की घोषणा और भूमिपूजन के साथ गोबरी नदी के स्थायी पुल की फाइल भी जमीन पर निर्माण तक पहुंचती है या नहीं।

दैनिक घटती-घटना का सवाल...अब जवाब चाहिए-दैनिक घटती-घटना ने पहले भी गोबरी नदी के टूटे पुल और अस्थायी रपटा को लेकर सवाल उठाए थे। अब उसी मामले का यह अगला अध्याय है,तब पुल टूटा था, फिर रपटा बनाया गया, रपटा बारिश में बह गया, अब सड़क चौड़ीकरण का भूमिपूजन हो चुका है,लेकिन जनता का सवाल आज भी वही है की गोबरी नदी का स्थायी पुल आखिर कब बनेगा? और इसके साथ दूसरा सवाल है की 15 लाख का रपटा अगर 15 दिन भी नहीं टिक पाया तो उसकी गुणवत्ता और जिम्मेदारी तय करने की कार्रवाई कहां तक पहुंची? तीसरा सवाल है की 30.45 करोड़ के टेंडर और करीब 25 करोड़ में काम मिलने की चर्चा के बीच सड़क निर्माण की गुणवत्ता की गारंटी कौन देगा?'और सबसे बड़ा सवाल'क्या करोड़ों की सड़क से पहले उस सड़क की सबसे बड़ी बाधा गोबरी नदी के पुल को प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए थी? भूमिपूजन हो गया है। अब जनता शिलापट्ट नहीं, सड़क और पुल दोनों को जमीन पर देखना चाहती है, डुमरिया-केवड़ा मार्ग का असली विकास तभी माना जाएगा, जब चौड़ी सड़क के साथ गोबरी नदी पर स्थायी पुल भी खड़ा हो और ग्रामीणों को हर मौसम में सुरक्षित आवागमन मिल सके।

पशु तस्करी में फरार आरोपी परवेश आलम गिरफ्तार,जेल भेजा

9 भैंसों को क्रूरतापूर्वक बूचड़खाने ले जाने का मामला...पूछताछ में तस्करी में संलिप्तता स्वीकारने का पुलिस का दावा

-संवाददाता-

रामचंद्रपुर/बलरामपुर,16 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। पशु तस्करी के मामले में फरार चल रहे आरोपी परवेश आलम (20) को रामचंद्रपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीक्षण निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज है।

9 भैंसों को बूचड़खाने ले जाने की शिकायत : पुलिस के अनुसार, 14 सितंबर 2026 को ग्राम औरंगा निवासी उदय कुमार सिंह (37) ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 9 रास मवेशियों (भैंसों) को क्रूरतापूर्वक मारते-पीटते हुए अवैध रूप से बूचड़खाने की ओर ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर दबिश दी और उसी दिन एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया था।

पूछताछ में संलिप्तता स्वीकारने का दावा : मामले की जांच के दौरान पुलिस ने दूसरे आरोपी परवेश आलम,पिता शौकत अली, निवासी ग्राम सुंदरपुर, थाना सनावल, को हिरासत में लिया।

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी ने पशु तस्करी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। इसके बाद पुलिस ने उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मामले में पुलिस की जांच जारी है।

ढाई माह पहले श्वान ने काटा,एंटी रेबीज नहीं लगवाया,युवक की मौत

गांव में जड़ी-बूटी से करा रहा था इलाज,हालत बिगड़ने पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया था भर्ती

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,16 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम पंपापुर निवासी 21 वर्षीय युवक की श्वान के काटने के करीब ढाई माह बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों के अनुसार श्वान के काटने के बाद युवक ने अस्पताल में उपचार नहीं कराया था और न ही एंटी रेबीज का टीका लगवाया था। वह गांव में ही जड़ी-बूटी से उपचार करा रहा था। हालत बिगड़ने पर उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराया गया था,जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार प्रदीप कुमार पिता रामधनी चौधरी (21) ग्राम पंपापुर का रहने वाला था। करीब ढाई माह पूर्व गांव में ही एक श्वान ने उसके हाथ में काट लिया था। श्वान के काटने के बाद प्रदीप ने अस्पताल जाकर उपचार नहीं कराया और एंटी रेबीज का टीका भी नहीं लगवाया। वह गांव में ही जड़ी-बूटी से उपचार कराता रहा। इसी बीच 14 सितंबर को उसके हाथ में अचानक असहनीय दर्द शुरू हो गया। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे शहर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे।

वहां एंटी रेबीज की आवश्यकता को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। इसके बाद परिजन प्रदीप को मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे और भर्ती कराया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजन सदमे में हैं। श्वान के काटने के बाद समय पर चिकित्सकीय उपचार और एंटी रेबीज नहीं लगवाने को लेकर भी मामला सामने आया है।

जामा मस्जिद चुनाव पर बड़ा फैसला...प्रक्रिया निरस्त,नए चुनाव तक इश्तियाक अहमद संभालेंगे कार्यवाहक सदर की जिम्मेदारी

जामा मस्जिद चुनाव निरस्त...अब नए सिरे से होगा चुनाव...वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कलेक्टर-एसडीएम को दिया निर्देश

विवादों के बीच जामा मस्जिद चुनाव पर लगा ब्रेक,नई चुनाव समिति करेगी प्रक्रिया तय,इश्तियाक अहमद संभालेंगे अंतरिम जिम्मेदारी

नए सिरे से बनेगी चुनाव समिति, 1 लाख तक खर्च कर सकेंगे कार्यवाहक सदर इश्तियाक अहमद

आपत्तियों के बाद जामा मस्जिद चुनाव निरस्त,वक्फ बोर्ड का फैसला,निष्पक्ष चुनाव के लिए नई समिति का होगा गठन

चुनाव रद्द,अब नई समिति और नई चुनाव प्रक्रिया,जामा मस्जिद की अंतरिम कमान इश्तियाक अहमद के हाथ,1 लाख से अधिक खर्च पर बोर्ड की अनुमति जरूरी

दैनिक घटती-घटना का बड़ा असर... जामा मस्जिद चुनाव प्रक्रिया निरस्त

वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने माना प्रक्रिया पर उठे सवाल,नए सिरे से चुनाव कराने के निर्देश

-शमरोज खान-

सूरजपुर,16 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

शहर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद के मुतवल्ली/सदर पद को लेकर चल रही चुनावी प्रक्रिया पर आखिरकार विराम लग गया है, चुनाव को लेकर लगातार सामने आ रही आपत्तियों और प्रक्रिया की निष्पक्षता पर उठ रहे सवालों के बीच छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ.सलीम राज सूरजपुर पहुंचे और वर्तमान चुनाव प्रक्रिया को निरस्त कर दिया, उन्होंने स्पष्ट किया कि अब चुनाव नए सिरे से कराया जाएगा और इसके लिए नई चुनाव समिति गठित की जाएगी।

वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने कलेक्टर एवं एसडीएम को नए सिरे से चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं,नई चुनाव समिति ही चुनाव की पूरी रूपरेखा तैयार करेगी और उसी के आधार पर मतदाता सूची,सदस्यता,नामांकन,आपत्ति, स्क्रूटनी,प्रचार,मतदान एवं परिणाम की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी,इस पूरे घटनाक्रम के बाद जामा मस्जिद चुनाव को लेकर चल रहा विवाद एक नए चरण में पहुंच गया है। अब सवाल यह नहीं रह गया कि पुरानी प्रक्रिया के तहत चुनाव कब होगा,बल्कि मुख्य सवाल यह है कि नई चुनाव समिति कौन होगी,मतदाता सूची कैसे तैयार होगी और निष्पक्ष चुनाव के लिए क्या नए नियम लागू किए जाएंगे।

जामा मस्जिद चुनाव तक इश्तियाक अहमद संभालेंगे कार्यवाहक सदर की जिम्मेदारी-शहर की पुरानी एवं प्रमुख जामा मस्जिद के चुनाव को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब अंतरिम व्यवस्था भी स्पष्ट हो गई है, वर्तमान चुनाव प्रक्रिया निरस्त किए जाने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया है कि जब तक जामा मस्जिद में नए सिरे से चुनाव संपन्न नहीं हो जाता,तब तक इश्तियाक अहमद कार्यवाहक सदर के रूप में मस्जिद की जिम्मेदारी संभालेंगे,वक्फ बोर्ड की ओर से तय इस व्यवस्था के तहत इश्तियाक अहमद चुनाव होने तक जामा मस्जिद की नियमित व्यवस्थाओं और आवश्यक संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगे,उन्हें 1 लाख तक खर्च करने का अधिकार रहेगा,वहीं,इस निर्धारित सीमा से अधिक राशि खर्च करने की स्थिति में वक्फ बोर्ड से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा,जामा मस्जिद चुनाव की प्रक्रिया को लेकर मतदाता सूची,चुनाव समिति और निष्पक्षता जैसे मुद्दों पर उठी आपत्तियों के बीच कार्य वाहक सदर की जिम्मेदारी स्पष्ट किए जाने को अंतरिम व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

चुनाव निरस्त होने के बाद सामने आई अंतरिम व्यवस्था-जामा मस्जिद के सदर/मुतवल्ली चुनाव को लेकर पहले से निर्धारित प्रक्रिया पर अलग-अलग स्तर पर आपत्तियां सामने आई थीं। मतदाता सूची, चुनाव समिति की भूमिका और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए गए थे,विवाद बढ़ने के बाद वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने सूरजपुर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और वर्तमान चुनाव प्रक्रिया को निरस्त करने का निर्णय लिया,इसके साथ ही अब चुनाव नए सिरे से कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी,नई चुनाव समिति गठित होगी और वही आगे की चुनावी रूपरेखा तय करेगी,लेकिन जब तक नई प्रक्रिया पूरी होकर निर्वाचित सदर की नियुक्ति नहीं हो जाती,तब तक मस्जिद की रोजमर्रा की व्यवस्था प्रभावित न हो,इसके लिए कार्यवाहक व्यवस्था लागू की गई है।

दैनिक घटती-घटना ने उठाए थे चुनाव प्रक्रिया पर सवाल-जामा मस्जिद चुनाव को लेकर दैनिक घटती-घटना ने चुनाव प्रक्रिया में सामने आ रही आपत्तियों और चुनाव समिति की भूमिका से जुड़े सवालों को प्रमुखता से उठाया था, रिपोर्ट में मतदाता सूची, सदस्यता,चुनाव समिति की निष्पक्षता और कथित विवादों को लेकर सवाल सामने रखे गए थे,इसी दौरान चुनाव समिति से संबंधित बताए जा रहे एक कथित ऑडियो को लेकर भी चर्चा तेज हुई थी,हालांकि किसी कथित ऑडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई थी और उस आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाना उचित नहीं है,लेकिन इन विवादों ने चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता को लेकर सवाल जरूर खड़े कर दिए थे, अब वक्फ बोर्ड द्वारा चुनाव प्रक्रिया निरस्त किए जाने के बाद पूरे मामले में नई प्रक्रिया शुरू होगी।

इश्तियाक अहमद को मिली अंतरिम जिम्मेदारी

वक्फ बोर्ड अध्यक्ष के अनुसार इश्तियाक अहमद नए चुनाव होने तक कार्यवाहक सदर के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे,इस दौरान उनका दायित्व जामा मस्जिद की नियमित व्यवस्था और आवश्यक कार्यों को संचालित करना होगा,चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्वाचित पदाधिकारी जिम्मेदारी संभालेंगे,इस अंतरिम व्यवस्था से यह भी स्पष्ट हो गया है कि चुनाव तक जामा मस्जिद के संचालन में प्रशासनिक शून्यता की स्थिति नहीं रहेगी।

आपत्तियों के बीच बोर्ड अध्यक्ष का सूरजपुर दौरा

जामा मस्जिद चुनाव को लेकर पिछले कई सप्ताह से विवाद की स्थिति बनी हुई थी, चुनाव प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची,सदस्यता,चुनाव समिति की भूमिका और कुछ प्रत्याशियों को लेकर आपत्तियां सामने आई थीं,कुछ सदस्यों ने चुनाव समिति के सदस्यों की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए वक्फ बोर्ड के समक्ष शिकायत की थी,शिकायत में चुनाव समिति के कुछ सदस्यों को हटाकर नई एवं निष्पक्ष समिति गठित करने की मांग की गई थी,मामला लगातार चर्चा में आने के बाद वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज सूरजपुर पहुंचे,उन्होंने संबंधित पक्षों से चर्चा की और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े विषयों की जानकारी ली, इसके बाद वर्तमान चुनाव प्रक्रिया को ही निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

पुराना चुनाव कार्यक्रम अब प्रभावी नहीं-जामा मस्जिद चुनाव के लिए पहले जारी समय-सारणी के अनुसार मतदान 10 अक्टूबर 2026 को कराया जाना प्रस्तावित था, उससे पहले दावा-आपत्ति,नामांकन, स्क्रूटनी और प्रचार की तिथियां भी निर्धारित की गई थीं, लेकिन वर्तमान चुनाव प्रक्रिया निरस्त किए जाने के बाद पुराना चुनाव कार्यक्रम प्रभावी नहीं रहेगा,अब नई चुनाव समिति के गठन के बाद नई समय-सारणी जारी होने की संभावना है, इसका अर्थ यह है कि पहले की मतदाता सूची, नामांकन प्रक्रिया और चुनाव कार्यक्रम को लेकर भी नई समिति को स्पष्ट निर्णय लेना होगा।

नई चुनाव समिति तय करेगी पूरी चुनावी रूपरेखा-वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने स्पष्ट किया है कि आगामी चुनाव के लिए नई चुनाव समिति गठित की जाएगी। यही समिति चुनाव की रूपरेखा तैयार करेगी, नई समिति के सामने सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पात्र मतदाताओं की पहचान और मतदाता सूची को लेकर स्पष्टता स्थापित करना होगा, इसके साथ ही सदस्यता की पात्रता, मतदाता सूची तैयार करने का आधार,नामांकन की शर्तें,प्रत्याशियों की पात्रता,दावा-आपत्ति की प्रक्रिया,स्क्रूटनी,मतदान की व्यवस्था,मतगणना और परिणाम घोषणा जैसे विषयों को स्पष्ट नियमों के साथ तय करना होगा।

जामा मस्जिद के सदस्यों को लेकर भी होगा स्पष्ट नियम-सूरजपुर में अलग-अलग क्षेत्रों में मस्जिदें हैं और स्थानीय लोगों के अनुसार प्रत्येक मस्जिद से जुड़े सदस्यों की अपनी व्यवस्था है,जामा मस्जिद शहर की प्रमुख एवं पुरानी मस्जिद होने के कारण यहां सदस्यता और सहभागिता का दायरा भी महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है,वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने संकेत दिया है कि जामा मस्जिद में व्यापक सहभागिता रहेगी, लेकिन चुनाव प्रक्रिया में कौन व्यक्ति मतदाता होगा और कौन प्रत्याशी बन सकेगा, इसके लिए स्पष्ट नियम बनाए जाएंगे, यही विषय पिछले चुनाव विवाद में भी महत्वपूर्ण रहा था,नई चुनाव समिति को इस विषय पर स्पष्टता लानी होगी ताकि चुनाव के दौरान किसी व्यक्ति की सदस्यता अथवा मतदान के अधिकार को लेकर विवाद न हो।

मुख्य मस्जिद है,इसलिए सहभागिता रहेगी-वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज के अनुसार जामा मस्जिद शहर की मुख्य मस्जिद है। इसलिए इसमें व्यापक स्तर पर सहभागिता की बात कही गई है,हालांकि इसका अर्थ यह नहीं होगा कि बिना निर्धारित पात्रता के कोई भी व्यक्ति मतदान अथवा चुनाव लड़ सकेगा। पात्रता और सदस्यता के नियम नई चुनाव समिति द्वारा तय किए जाएंगे और उसी के अनुसार चुनाव कराया जाएगा,यह व्यवस्था इसलिए भी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि पिछले चुनाव को लेकर कुछ लोगों ने दूसरे क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों के हस्तक्षेप का आरोप लगाया था।

चुनाव समिति निष्पक्ष होगी...बोर्ड अध्यक्ष-वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि नई चुनाव समिति को निष्पक्ष रखा जाएगा,उनके अनुसार चुनाव समिति का उद्देश्य किसी पक्ष विशेष को लाभ पहुंचाना नहीं, बल्कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना होगा, समिति को इस तरह गठित किए जाने की बात कही गई है जिससे किसी भी पक्ष को यह शिकायत न रहे कि चुनाव प्रक्रिया में भेदभाव किया गया है,नई समिति द्वारा तैयार की जाने वाली रूपरेखा ही आगे के चुनाव की आधारशिला होगी।

चुनाव तक वित्तीय और प्रशासनिक जिम्मेदारी का सवाल हुआ स्पष्ट-कार्यवाहक सदर के रूप में इश्तियाक अहमद की जिम्मेदारी तय किए जाने से अब चुनाव तक जामा मस्जिद के प्रशासनिक संचालन को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है,एक ओर कार्यवाहक सदर नियमित व्यवस्था संभालेंगे, वहीं दूसरी ओर बड़े वित्तीय निर्णयों पर वक्फ बोर्ड की अनुमति आवश्यक रहेगी,इससे चुनाव के बीच मस्जिद की व्यवस्था चलाने और बड़े खर्चों पर निगरानी रखने के लिए एक अंतरिम ढांचा तैयार हो गया है।

विवाद के बीच अब भरोसा कायम करना होगी नई समिति की चुनौती-जामा मस्जिद चुनाव को लेकर सामने आए विवाद के बाद अब नई चुनाव समिति के सामने केवल चुनाव कराने की जिम्मेदारी नहीं होगी, बल्कि चुनाव प्रक्रिया में सभी संबंधित पक्षों का विश्वास कायम करना भी महत्वपूर्ण होगा, मतदाता सूची और सदस्यता को लेकर स्पष्ट नियम,सभी पात्र सदस्यों को समान अवसर तथा चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता इस पूरे चुनाव की अहम कड़ी होगी,वहीं,कार्यवाहक सदर की वित्तीय सीमा तय होने के बाद चुनाव तक होने वाले बड़े खर्चों पर वक्फ बोर्ड की निगरानी बनी रहेगी।

अब जामा मस्जिद में नई व्यवस्था के साथ नए चुनाव का इंतजार-वर्तमान चुनाव प्रक्रिया निरस्त होने के बाद अब जामा मस्जिद का चुनाव नए सिरे से होगा,इश्तियाक अहमद तब तक कार्यवाहक सदर की जिम्मेदारी संभालेंगे, जब तक नई चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हो जातीवहीं ?1 लाख तक के खर्च की अनुमति और इससे अधिक खर्च के लिए वक्फ बोर्ड की पूर्व स्वीकृति की व्यवस्था के बीच अब अगली बड़ी कार्रवाई नई चुनाव समिति के गठन की होगी, पुराना चुनाव निरस्त, कार्यवाहक सदर की जिम्मेदारी तय–अब नई समिति, नई रूपरेखा और नए चुनाव पर टिकी सूरजपुर की नजर।

अब निगाहें वक्फ बोर्ड और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर-वर्तमान चुनाव प्रक्रिया निरस्त किए जाने के बाद अब अगला चरण नई चुनाव समिति के गठन का होगा, इसके बाद समिति चुनाव की नई रूपरेखा तैयार करेगी और उसी के आधार पर नई समय-सारणी जारी की जाएगी,कलेक्टर एवं एसडीएम को नए सिरे से चुनाव कराने के निर्देश दिए जाने के बाद प्रशासन की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है, पुरानी प्रक्रिया पर लगा विराम, अब नई समिति और नए नियमों के साथ जामा मस्जिद के सदर का चुनाव होगा, एक लाख रुपये तक कार्यवाहक सदर के खर्च अधिकार और उससे अधिक राशि के लिए वक्फ बोर्ड की अनुमति की व्यवस्था के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नई चुनाव समिति कितनी पारदर्शी होगी और नई चुनाव प्रक्रिया पर सभी पक्ष कितना भरोसा कर पाएंगे।

15 वें वित्त की राशि निकली...शौचालय अधूरा,निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल

रोजगार सहायक की देखरेख में शुरू हुआ था काम,आधी से अधिक राशि आहरित होने के बाद निर्माण ठप्प...

सुदामा राजवाड़े

कुसमी,16 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

ग्राम पंचायत कोरंधा के शासकीय हाईस्कूल परिसर में 15 वें वित्त आयोग की राशि से स्वीकृत शौचालय निर्माण प्रशासनिक निगरानी पर सवाल खड़े कर रहा है। करीब 3 लाख रुपए की लागत से प्रस्तावित शौचालय का निर्माण पिछले दो-तीन वर्षों से अधूरा पड़ा है। निर्माण के लिए स्वीकृत राशि में से आधे से अधिक राशि आहरित होने की जानकारी है, इसके बावजूद विद्यार्थियों की सुविधा से जुड़ा यह काम अब तक पूरा नहीं हो सका है। जानकारी के अनुसार शौचालय निर्माण का काम ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक अभिषेक साहू की देखरेख में कराया जा रहा था। निर्माण शुरू होने के बाद भवन का कुछ हिस्सा तैयार किया गया, लेकिन इसके बाद लंबे समय से काम बंद पड़ा है। स्कूल परिसर में अधूरी पड़ी संरचना अब जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है।

राशि निकली,फिर काम क्यों रुका?

आरईएस विभाग के इंजीनियर अमरीश यादव से मिली जानकारी के अनुसार शौचालय निर्माण की स्वीकृत लागत करीब 3 लाख रुपए है। इसमें से आधे से अधिक राशि आहरित हो चुकी है। उनका कहना है कि शेष राशि आहरित नहीं होने के कारण फिलहाल निर्माण रुका हुआ है और जल्द काम शुरू कराने का प्रयास किया जाएगा।

हालांकि,सवाल यह है कि यदि निर्माण के लिए पर्याप्त राशि पहले ही आहरित हो चुकी थी,तो काम लंबे समय तक अधूरा क्यों पड़ा रहा? वहीं, निर्माण की प्रगति और खर्च की निगरानी किस स्तर पर की गई,यह भी जांच का विषय है।

निर्माण की गुणवत्ता भी घेरे में : अधूरे निर्माण के साथ मौके पर काम की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थल पर ईंटों की चिनाई और मसाले की भराई में अनियमितता, कंक्रीट में छिद्र व उखड़ाव,लोहे की छड़ों का खुला दिखाई देना तथा दीवार और छत के जोड़ में खामियां नजर आने की बात सामने आई है। हालांकि इन खामियों के आधार पर निर्माण को तकनीकी रूप से घटिया घोषित नहीं किया जा सकता। इसकी वास्तविक गुणवत्ता और संरचनात्मक मजबूती का निष्कर्ष संबंधित तकनीकी विभाग की जांच और परीक्षण के बाद ही सामने आएगा।

जिम्मेदारों ने जांच का भरोसा दिया : ग्राम पंचायत कोरंधा के सरपंच लालू राम ने बताया कि शौचालय निर्माण रोजगार सहायक अभिषेक साहू के माध्यम से कराया जा रहा है। उनसे काम पूरा कराने के लिए लगातार कहा जा रहा है और जल्द निर्माण शुरू कराने का प्रयास किया जाएगा। वहीं जनपद पंचायत के सीईओ मुन्नालाल ने कहा कि मामले की जानकारी उनके संज्ञान में आई है। राशि जारी होने के बाद भी निर्माण अधूरा है तो पूरे मामले की जांच कराई जाएगी।

तीन साल की देरी पर उठ रहे ये सवाल

* करीब 3 लाख रुपए का शौचालय निर्माण दो-तीन साल में पूरा क्यों नहीं हुआ?
* आधी से अधिक राशि आहरित होने के बावजूद निर्माण कार्य क्यों बंद पड़ा रहा?
* निर्माण की गुणवत्ता की नियमित तकनीकी निगरानी किसने की?
* अधूरे निर्माण से विद्यार्थियों को हो रही परेशानी की जिम्मेदारी किसकी है?
* यदि जांच में अनियमितता या घटिया निर्माण की पुष्टि होती है तो जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होगी?

अब निगाह जनपद प्रशासन की प्रस्तावित जांच पर है। जांच में यदि निर्माण की गुणवत्ता, राशि के आहरण और कार्य की प्रगति में गड़बड़ी सामने आती है तो जिम्मेदारी तय करना जरूरी होगा। फिलहाल विद्यार्थियों की सुविधा के लिए स्वीकृत शौचालय वर्षों से अधूरा पड़ा है और उसे पूरा कराने का इंतजार जारी है।

CMYK

खत्म हुआ इंतजार,अल्लू अर्जुन की राका पर आया लेटेस्ट अपडेट,इस महीने में दिखेगी पहली झलक

जवान फिल्म डायरेक्टर एटली की मोस्ट अवेटेड फिल्म राका को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट सामने आ रहा है।

फिल्म पुष्पा 2 के बाद से साउथ फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन बड़े पर्दे से दूर हैं। उनकी अगली फिल्म का नाम राका है, जिसका निर्देशन बॉलीवुड सुपरस्टार शाह रुख खान के करियर की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान बनाने वाले निर्देशक एटली कर रहे हैं। लंबे समय से अल्लू अर्जुन की राका का नाम चर्चा में बना हुआ है। अब खबर आ रही है कि राका को लेकर मेकर्स ने आधी से अधिक तैयारी कर ली है और आने वाले इस महीने में वह पहली झलक भी पेश करेंगे।

अल्लू अर्जुन की राका पर आया लेटेस्ट अपडेट

बुधवार को अल्लू अर्जुन की राका फिल्म के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर फिल्म का एक टाइटल पोस्टर शेयर किया है। इसके साथ ही फिल्म से जुड़ा जरूरी ताजा अपडेट भी साझा किया है। ट्वीट में लिखा है...करीब तीन महीने बाद दिसंबर 2026 में राका की दुनिया की पहली झलक देखने को मिलेगी। हालांकि,मेकर्स ने ये साफ नहीं किया है कि दिसंबर में मूवी का टीजर रिलीज किया जाएगा या फिर कोई प्रोमो वीडियो। इससे पहले राका से अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक पोस्टर पहले ही रिलीज किया जा चुका है। जिसे देखने के बाद एटली की इस अपकमिंग मूवी को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर बनी हुई है। बात की जाए राका के बारे में तो इसे एक फेंटेसी,साई-फाई एक्शन ड्रामा फिल्म बताया जा रहा है, जिसमें अल्लू अर्जुन का ऐसा अवतार देखने को मिलेगा,जो शायद पहले कभी बड़े पर्दे पर देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा चर्चा की जाए राका की कास्ट के बारे में तो इसमें अल्लू अर्जुन के अलावा दीपिका पादुकोण,रश्मिका मंदाना,जाह्नवी कपूर और मृणाल ठाकुर जैसे कई कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

कब रिलीज होगी राका

फिलहाल फिल्म अल्लू अर्जुन स्टारर राका की रिलीज डेट को लेकर मेकर्स की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 2027 के अंत तक इस बहुचर्चित फिल्म को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया जा सकता है।

विजय-एक्ट्रेस तृषा फिर साथ दिखे, दिग्गज अभिनेत्री की सलाह से मचा बवाल

क्या सिर्फ दोस्ती की वजह से दो लोग हर जगह साथ नजर आ सकते हैं,या बड़े पद पर पहुंचने के बाद रिश्तों को लेकर सावधानी भी जरूरी हो जाती है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता विजय के साथ अभिनेत्री तृषा कृष्णन की हालिया मौजूदगी ने एक बार फिर दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चाओं को हवा दे दी है। इसी बीच दिग्गज अभिनेत्री अंबिका की तृषा को दी गई सलाह भी चर्चा में आ गई है।

सिल्वरस्टोन रेस में फिर साथ दिखे विजय-तृषा

ब्रिटेन के सिल्वरस्टोन में मिशेलिन ले मैन्स कप रेस के दौरान विजय और तृषा एक बार फिर साथ नजर आए। विजय ने इस रेस की शुरुआत फ्लैग ऑफ करके की। इस इवेंट में साउथ स्टार अजित कुमार भी रेस में शामिल हुए थे। रेस से सामने आए वीडियो में तृषा विजय के साथ बालकनी में दिखाई दीं। सोशल मीडिया पर सामने आए दूसरे वीडियो में भी दोनों को रेस का आनंद लेते हुए देखा गया। इस दौरान विजय की अजित कुमार से मुलाकात और रेस को हरी झंडी दिखाने के वीडियो भी सामने आए। हालांकि,इन सबके बीच विजय के साथ तृषा की मौजूदगी ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। दोनों के बीच लंबे समय से चले आ रहे अफेयर रूमर्स के कारण एक बार फिर सोशल मीडिया पर उनके रिश्ते को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं।

अंबिका ने तृषा को दी सावधानी बरतने की सलाह

इसी चर्चा के बीच दिग्गज अभिनेत्री अंबिका ने तृषा को सार्वजनिक जगहों पर विजय के साथ नजर आने को लेकर अपनी राय रखी। साउथ की वेबसाइट रेडपिक्स को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि संभव है तृषा दोनों को सिर्फ दोस्त मानती हों और इसलिए आलोचना की परवाह न करती हों। अंबिका के मुताबिक, विजय अब एक बड़े पद पर हैं। ऐसे में अगर किसी जगह दोनों के साथ दिखने से तृषा को आलोचना या परेशानी का सामना करना पड़े अथवा इसका नकारात्मक असर विजय पर पड़े, तो वह उनकी जगह होतीं तो पीछे हट जातीं। उन्होंने कहा कि वह ऐसी स्थिति में विजय के लिए मुश्किल पैदा नहीं करना चाहेंगी।

बादशाह संग 5 महीने में टूटी ईशा रिखी की शादी

पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी पिछले दिनों रैपर बादशाह के साथ अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में थीं। ईशा और बादशाह ने मार्च में शादी की थी और शादी के पांच महीने में ही दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। बिग बॉस 20 में पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी ने बतौर कंटेस्टेंट एंट्री ली है। ईशा पिछले दिनों रैपर बादशाह के साथ अपने रिश्ते को लेकर सुर्खियों में थीं। मार्च में बादशाह और ईशा रिखी की शादी की खबरें आई थीं। एक्ट्रेस की मां ने कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर कर दोनों की शादी का ऐलान किया था। लेकिन, खुद ईशा और बादशाह ने अपनी शादी पर कभी खुलकर बात नहीं की। इसी बीच इस महीने की शुरुआत में दोनों ने पोस्ट साझा करते हुए अपने तलाक का ऐलान कर दिया, जिसने सबको चौंका दिया। अब जब ईशा अभी बिग बॉस 20 में नजर आ रही हैं तो हर किसी की नजरें उन पर टिकी रहती हैं। यूं तो सीधे तौर पर ईशा रिखी ने कभी बादशाह का नाम नहीं लिया, लेकिन हाल ही में को-कंटेस्टेंट कनिका मान के साथ बातचीत में उन्होंने इशारों-इशारों में बताया कि रिलेशनशिप में उन्हें इमोशनली और फिजिकली, दोनों तरह से धोखा मिला।

ईशा रिखी का छलका दर्द

ईशा रिखी कनिका मान से बातचीत में कहती हैं- कनिका जब मेरे पास कोई आकर कहता है ना कि कनिका ऐसी है, मैं तब तक विश्वास नहीं करती जब तक अपनी आंखों से न देख लूं। मैं रिलेशनशिप में भी ऐसी ही हूं। अगर कोई मेरे पास आकर कुछ कहेगा तो मैं उससे कहूंगी या तो सबूत लेकर आओ या फिर मुझे परेशान मत करो। लेकिन जब ये (शादी) खत्म हुआ, तब मुझे पता चला कि यहां तो मेरा कट गया।

क्या ईशा रिखी को रिश्ते में मिला धोखा?

बातचीत के दौरान कनिका मान, ईशा से पूछती हैं कि क्या उन्हें रिश्ते में कभी इमोशनली या फिजिकली चीट किया गया है? जवाब में ईशा ने कहा-वो सभी.. वो जो बीच में लटकना होता है न,उस सिचुएशन में मेरे लिए फंसना बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे मैं तुमसे कह रही हूं कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और तुम्हें सारी बेस्ट फ्रेंड वाली फील दे रही हूं। मैं तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड की तरह दिखा रही हूं,लेकिन बाद में पता चलता है कि वह कभी आपकी बेस्ट फ्रेंड थी ही नहीं। मैं ये जो सारी चीजें प्राइवेट सर्कल में कर रही हूं,क्योंकि तेरी और भी बहुत सी बेस्ट फ्रेंड हैं।

कनिका मान और ईशा रिखी के बीच की बातचीत

जब कनिका ने ईशा से पूछा कि क्या और भी बेस्ट फ्रेंड थीं, तो ईशा कहती हैं- हां, पर वो एक-दो दिन चिल करने वाली थीं। लेकिन तुझे बेस्ट फ्रेंड बनाना ही नहीं था,तू तो बस गेम खेल रही थी मेरे साथ। सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि मैं इतनी सॉफ्ट और अच्छी हूं इसलिए तुम अपनी जिंदगी में मुझे चाहते हो, क्योंकि तुम्हें ये चीजें किसी और से नहीं मिल रहीं। आप मेरे साथ रहना चाहते हैं,लेकिन अपनी आजादी भी चाहते हैं। तुम मेरे साथ कुछ खास लोगों के साथ ही घूमते-फिरते हो, और बाद में मुझे पता चलता है कि तुम मुझे एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे थे जो असल में कभी थी ही नहीं।

शादीशुदा मर्दों से चक्कर चलाने वाली महिलाओं पर भड़कीं तनीषा मुखर्जी

तनीषा मुखर्जी ने शादीशुदा पुरुषों से अफेयर रखने वाली महिलाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसे फेमिनिज्म नहीं कहा जा सकता। उन्होंने ऐसे मामलों में पुरुष और महिला,दोनों की जिम्मेदारी पर जोर दिया।

काजोल की बहन और बॉलीवुड एक्ट्रेस तनीषा मुखर्जी सोशल मीडिया पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए जानी जाती हैं। वह अक्सर अपने एक्स अकाउंट पर सामाजिक मुद्दों और महिलाओं से जुड़े विषयों पर खुलकर अपनी बात रखती हैं। अब तनीषा ने शादीशुदा पुरुषों के साथ रिश्ते में रहने वाली महिलाओं को लेकर एक पोस्ट शेयर की है। अपने बयान में उन्होंने ऐसी महिलाओं को फेमिनिस्ट मानने से इनकार किया और कहा कि किसी शादीशुदा पुरुष के साथ अफेयर रखना उसकी पत्नी के सम्मान को ठेस पहुंचाने जैसा है।

तनीषा ने महिलाओं को लेकर क्या कहा?

तनीषा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि उनकी नजर में जो महिलाएं जानबूझकर शादीशुदा पुरुषों के साथ अफेयर करती हैं,उन्हें फेमिनिस्ट नहीं कहा जा सकता। उनका मानना है कि इस तरह के रिश्ते में उस पुरुष की पत्नी के अधिकारों और भावनाओं की अनदेखी होती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति के लिए केवल महिला को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है,बल्कि शादीशुदा पुरुष भी उतना ही जिम्मेदार है। एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में लिखा कि अगर कोई पुरुष शादीशुदा होने के बावजूद किसी दूसरी महिला के साथ रिश्ता बनाता है तो उसके चरित्र और फैसले पर भी सवाल उठना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो महिलाएं किसी शादीशुदा पुरुष के पीछे जाती हैं,उन्हें बच्चों के लिए रोल मॉडल के तौर पर पेश नहीं किया जाना चाहिए। अपने इस पोस्ट के आखिर में उन्होंने हैशटैग के साथ लिखा कि उन्होंने जो कहना था,साफ-साफ कह दिया।

सोशल मीडिया यूजर्स ने किया समर्थन

तनीषा के इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली,लेकिन कई लोगों ने उनके विचार का समर्थन भी किया। कुछ यूजर्स ने कमेंट में कहा कि ऐसे मामलों में पति और दूसरी महिला,दोनों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। एक यूजर ने तनीषा की बात से सहमति जताते हुए लिखा कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी शादी को तोड़ने की कोशिश करता है तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, फिर चाहे वह पुरुष हो या महिला। कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में दिल और फूल वाले इमोजी के जरिए भी अपनी प्रतिक्रिया दी।

पहले भी फेमिनिज्म पर रख चुकी हैं अपनी राय

तनीषा मुखर्जी इससे पहले भी फेमिनिज्म और महिलाओं के सम्मान जैसे मुद्दों पर अपनी राय जाहिर कर चुकी हैं। पिछले साल एक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान उन्होंने भारत में महिलाओं के सम्मान और संस्कृति को लेकर अपने विचार साझा किए थे। तनीषा ने कहा था कि भारतीय समाज में महिलाओं के सम्मान की परंपरा काफी मजबूत रही है। उन्होंने माना कि देश में महिलाओं से जुड़ी कुछ समस्याएं जरूर हैं, लेकिन उन्हें केवल संस्कृति में महिलाओं के प्रति सम्मान की कमी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। बातचीत के दौरान उन्होंने हिंदू धार्मिक परंपराओं का उदाहरण देते हुए कहा था कि इनमें महिला शक्ति और सम्मान की अवधारणा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उन्होंने भगवान कृष्ण-राधा और भगवान शिव-माता पार्वती के उदाहरण देते हुए कहा था कि भारतीय धार्मिक परंपराओं में महिलाओं के सम्मान की बात लंबे समय से मौजूद रही है। हालांकि,उनके इन विचारों पर अलग-अलग लोगों की अपनी राय हो सकती है।

खेल-समाचार

डब्ल्यूपीएल ऑक्शन को लेकर बड़ा ऐलान, अगले महीने कोच्चि में लगेगी खिलाड़ियों पर बोली

नई दिल्ली,16 सितम्बर 2026। वूमेंस प्रीमियर लीग के अगले सीजन से पहले ऑक्शन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। डब्ल्यूपीएल के ऑक्शन का अगले महीने आयोजन होगा। ऑक्शन किस शहर में होगा, इसका भी खुलासा हो गया है। वूमेंस प्रीमियर लीग के अगले सीजन की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। खिलाड़ियों के रिटेंशन और रिलीज से लेकर ऑक्शन तक की तस्वीर धीरे-धीरे साफ होने लगी है। बीसीसीआई ने 16 सितंबर को डब्ल्यूपीएल की पांचों फ्रेंचाइजियों को सीजन-5 के ऑक्शन की तारीख और वेन्यू की जानकारी दी है। खिलाड़ियों का ऑक्शन 28 अक्टूबर को कोच्चि में आयोजित होगा। बीसीसीआई ने बुधवार को सभी पांच टीमों को ऑक्शन से जुड़ी जानकारी औपचारिक रूप से साझा की। अब फ्रेंचाइजियों के पास अपनी टीम में बदलाव करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। सभी टीमों को 28 सितंबर तक अपने खिलाड़ियों के रिटेंशन और रिलीज पर फैसला करना होगा। इससे पहले इंडियन प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल के ऑक्शन को लेकर बड़ी खबर सामने आई।

ऑक्शन से पहले रिटेंशन होगा अहम

डब्ल्यूपीएल के एक स्क्वाड में अधिकतम 18 खिलाड़ी हो सकते हैं। इनमें अधिकतम 6 विदेशी खिलाड़ियों को शामिल किया जा सकता है। मौजूदा चक्र के लिए टीमों की सैलरी कैप 15 करोड़ रुपये तय की गई है। ऐसे में ऑक्शन से पहले रिलीज और रिटेन किए जाने वाले खिलाड़ियों के फैसले पर सभी फ्रेंचाइजियों की नजर रहेगी।

ऑक्शन की तारीख सामने आने के साथ ही अगले सीजन के वेन्यू को लेकर भी तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। आगामी सीजन के लिए मुंबई और वडोदरा वेन्यू के तौर पर चुने जाने की पूरी संभावना है। डब्ल्यूपीएल का अगला सीजन भी पिछले साल की तरह जनवरी-फरवरी के दौरान आयोजित किए जाने की उम्मीद है।

वाराणसी को भी कुछ मुकाबलों की मेजबानी मिलने की चर्चा थी, लेकिन फिलहाल इसकी संभावना कम मानी जा रही है। शहर में नया स्टेडियम तैयार हो रहा है और डब्ल्यूपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट के मुकाबले वहां कराने से पहले मैदान की तैयारियों को घरेलू क्रिकेट मैचों के जरिए परखा जाना जरूरी होगा। डब्ल्यूपीएल से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, वाराणसी में मैच कराने का फैसला पूरी तरह स्टेडियम की तैयारियों पर निर्भर करेगा। मौजूदा स्थिति में वहां लीग के मुकाबले होने की संभावना काफी कम है।

मुंबई और वडोदरा होंगे वेन्यू

पिछले सीजन की तरह मुंबई का सीसीआई और वडोदरा का कोटांबी स्टेडियम आगामी सीजन के लिए मेन वेन्यू होंगे। सीजन-4 के मुकाबले भी इन्हीं दोनों जगहों पर खेले गए थे और 5 फरवरी को वडोदरा में फाइनल आयोजित हुआ था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु डब्ल्यूपीएल की मौजूदा चैंपियन टीम है। अब सभी टीमों की नजर 28 अक्टूबर को होने वाले ऑक्शन पर होगी,जहां अगले सीजन के लिए टीमों को मजबूत करने की कवायद देखने को मिलेगी।

एफ1 ने 24 ग्रां प्री और 10 स्प्रिंट इवेंट्स वाले 2027 कैलेंडर की घोषणा की...

लंदन,16 सितम्बर 2026। विश्व मोटरस्पोर्ट परिषद द्वारा अनुमोदन के बाद,फॉर्मूला 1 और अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल महासंघ (एफआईए, फेडरेशन इंटरनेशनेल डी लऑटोमोबाइल) ने 2027 एफआईए फॉर्मूला वन विश्व चैम्पियनशिप कैलेंडर की घोषणा की है, जिसमें 22 देशों में 24 ग्रांड प्रिक्स और 10 स्प्रिंट इवेंट शामिल हैं,एक बयान में कहा गया है। चैम्पियनशिप की पहली रेस बहरीन में होने से पहले, प्री-सीजन टेस्टिंग 24 से 27 फरवरी तक बहरीन में होगी,जिसके बाद सऊदी अरब में रेस होगी। इसके बाद कैलेंडर ऑस्ट्रेलिया,जापान और चीन की ओर बढ़ता है,जिसके बाद मियामी और कनाडाई ग्रांड प्रिक्स होते हैं। यूरोपीय चरण में मोनाको के बाद जून में पुर्तगाल में फॉर्मूला 1 की वापसी शामिल है,जबकि अक्टूबर में अजरबैजान और सिंगापुर के बीच तुर्की कैलेंडर में फिर से शामिल होगा। सीज़न के समापन चरण में ऑस्टिन, मैक्सिको सिटी, साओ पाउलो और लास वेगास में रेस होंगी,जिसके बाद कतर और अबू धाबी में अंतिम दो राउंड होंगे। पांच महाद्वीपों में फैले ऐतिहासिक स्थलों और प्रमुख वैश्विक गंतव्यों को एक साथ लाते हुए, 2027 का कैलेंडर वैश्विक खेल और मनोरंजन मंच के रूप में फॉर्मूला 1 के निरंतर विकास को दर्शाता है, साथ ही पूरे सीज़न में आयोजनों के अधिक कुशल भौगोलिक प्रवाह के माध्यम से इसके दीर्घकालिक स्थिरता लक्ष्यों का समर्थन करता है।

लाहौल में शुरू हुई अंडर-19 रग्बी ट्रेनिंग हिमाचल स्कूल गेम्स में शामिल करेगा खेल

लाहौल-स्पीति,16सितम्बर 2026। रग्बी एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में रग्बी सचमुच नई ऊंचाइयों को छू रहा है। समुद्र तल से 9,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित लाहौल-स्पीति के त्रिलोकनाथ में अंडर-19 खिलाड़ियों के लिए व्यवस्थित कोचिंग और टैलेंट की पहचान करने का काम शुरू हो गया है। RAHP के कोच-सह-चयनकर्ता नवप्रीत सिंह,जो हिमाचल प्रदेश राज्य रग्बी टीम के कोच भी हैं,स्कूली बच्चों के लिए एक रिफ्रेशर कोर्स आयोजित करने और अंडर-19 लड़कों और लड़कियों की रग्बी टीमों के लिए होनहार टैलेंट की पहचान करने के लिए त्रिलोकनाथ के सरकारी स्कूल पहुंचे। यह पहल लाहौल क्षेत्र में चल रही स्कूल स्पोर्ट्स मीट के साथ-साथ आयोजित की जा रही है,जिसमें 19 स्कूलों के लगभग 150 छात्र भाग ले रहे हैं।

लियोनेल मेसी अर्जेंटीना की टीम में

नई दिल्ली,16 सितम्बर 2026। लियोनेल मेसी अगले महीने ब्यूनस आयर्स के एस्टाडियो मोन्यूमेंटल में बेनिन के खिलाफ होने वाले एक मैत्री मैच में खेलेंगे। अर्जेंटीना के लिए आधिकारिक तौर पर मेसी का यह आखिरी मैच होगा। एफए अध्यक्ष क्लाउडियो टैपिया ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमने दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ी,हमारी नेशनल टीम के आइकॉन,हमारे कप्तान लियोनेल आंद्रेस मेसी को अर्जेंटीना में एक अच्छी फेयरवेल के लिए बुलाया है।अर्जेंटीना एफए ने कहा, लियोनेल मेसी,रोड्रिगो डी पॉल और जियोवानी लो सेल्सो 6 अक्टूबर को होने वाले आखिरी फ्रेंडली मैच के लिए टीम में शामिल होंगे। घरेलू लीग से बुलाए गए खिलाड़ियों की सूची शुक्रवार को घोषित की जाएगी। मेसी ने पिछले महीने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास का ऐलान किया था। संन्यास के ऐलान के साथ ही उनके 20 साल के अर्जेंटीना करियर का अंत हो गया। अर्जेंटीना टीम के साथ मेसी ने एक वर्ल्ड कप, दो कोपा अमेरिका खिताब जीते और देश के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। मेसी ने 31 अगस्त को लिखा,फाइनल के बाद से जो समय बीत चुका है, और इस पर बहुत सोचने के बाद, मैं सबको बताना चाहता हूं कि मैं अर्जेंटीना की नेशनल टीम से रिटायर हो रहा हूं। यह एक ऐसा फैसला था जिससे दुःख हुआ और अब भी बहुत दुःख होता है लेकिन मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है। मैं कसम खाता हूं कि मैंने हमेशा अपना सब कुछ दिया। सिर्फ इन पिछले कुछ सालों में नहीं जब हमने सब कुछ जीता,बल्कि उससे पहले भी। मैंने हमेशा इस जर्सी के लिए मैदान पर सब दिया,ताकि आपको खुशी मिल सके और फुटबॉल के जरिए आपको अर्जेंटीना का होने पर गर्व महसूस हो। 39 साल के आठ बार के बैलन डी ओर विनर, जो अभी एमएलएस में इंटर मियामी के लिए खेलते हैं,अर्जेंटीना के ऑल-टाइम लीडिंग स्कोरर और सबसे ज्यादा कैप्ड प्लेयर हैं। मेसी ने 207 मैचों में 125 गोल किए हैं। मेसी ने 2005 में 18 साल की उम्र में अर्जेंटीना के लिए डेब्यू किया था। उन्होंने एल्बिसेलेस्टे को ब्राजील 2014 में रनर-अप और कतर 2022 में टाइटल जिताने के लिए प्रेरित किया। इस साल की शुरुआत में अपने आखिरी फीफा वर्ल्ड कप में,मेसी ने आठ गोल और चार असिस्ट करके लियोनेल स्कालोनी की टीम को फाइनल तक पहुंचाया। फाइनल में अर्जेंटीना को स्पेन से 1-0 से हार का सामना करना पड़ा था। अर्जेंटीना की नेशनल टीम 21 सितंबर से 6 अक्टूबर तक तीन अंतरराष्ट्रीय मैत्री मैच खेलेगी। पहला मैच बुधवार,30 सितंबर को कॉर्डोबा प्रोविंस के मारियो अल्बर्टो केम्पेस स्टेडियम में बोलीविया के खिलाफ होगा। बाकी दो मैच 3 अक्टूबर को रिवर प्लेट स्टेडियम में बुर्किना के खिलाफ और फासो में,6 अक्टूबर को बेनिन के खिलाफ होगा।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2, जिला सरगुजा (छ0ग0)

रा0प्र0क्र0 / ब-121 / 2023-24

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय जिला दण्डाधिकारी,सरगुजा,अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0) के द्वारा अपने कार्यालयीन पत्र कमांक- 118/लायसेंस शाखा/2026 अम्बिकापुर दिनांक 13/08/2026 के द्वारा उप महाप्रबंधक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, प्रथम तल बाजपेयी पविलियन व्यपार बिहार रोड बिलासपुर के पत्र कमांक एच.पी.सी.एल./बी.एस.पी. आर. आर.ओ./आर.ई.टी./सेल्स/डी.पी./01 दिनांक 31/7/2026 के परिपेक्ष्य में रिटेल आउटलेट मेसर्स दरिमा पेट्रोल पम्प को ग्राम चठिरमा तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0) स्थित भूमि खसरा क्रमांक- 389 / 9 रकबा 0.123 हे0 भूमि, जिसके पार्टनर खगेन्द्र सिंह निवासी महेशपुर तहसील प्रेमनगर जिला सूरजपुर एवं विकास तिवारी निवासी आजाद वार्ड कमांक- 16, चर्च रोड़ अम्बिकापुर है,पर स्थान्तरित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किये जाने के संबंध में स्थल निरीक्षण कर स्पष्ट अभिमत सहित जांच प्रतिवेदन चाहा गया है। प्रकरण के साथ हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अनुमोदित नक्शा (ब्लू प्रिन्ट), एव खसरा / बी-1 तथा अन्य सुसंगत दस्तावेजो की प्रति संलग्न है। जो जांच व प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ हैं। जो जांच व प्रतिवेदन हेतु प्राप्त हुआ है।

उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 30/9/2026 को न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 15/09 / 2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील

अतिरिक्त तहसीलदार
,अंबिकापुर-2

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ-6/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सावर्णी कुमार दुबे आ.स्व. तीरथ प्रसाद दुबे निवासी भट्ठापारा अम्बिकापुर, तह0 अ0पुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि आवेदक के पिता के स्वामित्व व अधिपत्य की नगर अ0पुर मोहल्ला भट्ठापारा, शीट नं. 11 स्थित प्लॉट नंबर 4525/6 रकबा 0.05 एकड़ भूमि है। आवेदक के पिता तीरथ प्रसाद दुबे की मृत्यु दिनांक 26.11.2019 को हो गई तउपरांत आवेदित भूखण्ड से मृत्तक तीरथ प्रसाद दुबे का नाम विलोपित कर उनके उत्तराधिकारियों के नाम से फौती नामांतरण किये जाने हेतु आवेदक द्वारा मृत्तक तीरथ प्रसाद दुबे के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है ।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा/ आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 30/09/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा / अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक-16/09/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सील

नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

झीरम घाटी में नक्सली हमले के 10 दोषियों को मृत्युदंड

सीएम साय ने कहा...न्याय की हुई जीत,हमले में जान गंवाने वाले नेताओं,सुरक्षाकर्मियों और आम नागरिकों को दी श्रद्धांजलि

रायपुर,16 सितम्बर 2026। झीरम घाटी हत्याकांड मामले में जगदलपुर की एनआईए कोर्ट ने 10 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। 25 मई 2013 को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर नक्सली हमला हुआ था। इसमें कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल,महेंद्र कर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल समेत 29 लोगों की मौत हुई थी। करीब 13 साल चली सुनवाई के दौरान 101 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया गया। जज ने अपने फैसले में कहा है कि आदेश की पुष्टि हाईकोर्ट करेगा। दोषियों को 30 दिन के अंदर हाईकोर्ट में अपील करने का अधिकार है। अभियोजन पक्ष ने दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी,जबकि बचाव पक्ष ने सजा कम करने की दलील दी थी। सभी दोषी अभी केंद्रीय जेल में बंद हैं। अदालत ने कुल 11 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई की थी। मुकदमे के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी,जिसके बाद अदालत ने शेष 10 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई जारी रखी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने वर्ष 2015 में लगभग 1000 पन्नों का आरोप पत्र अदालत में पेश किया था। अभियोजन पक्ष ने आरोपियों का दोष साबित करने के लिए पूरी सुनवाई के दौरान 101 गवाहों के बयान दर्ज कराए थे। इधर,एनआईए की विशेष अदालत से दोषियों को मृत्युदंड की सजा मिलने के बाद अब मामले की अगली कानूनी प्रक्रिया पर सबकी निगाहें हैं। आरोपी पक्ष फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है।

25 मई 2013 को हुआ था झीरम नक्सली हमला

13 साल पहले बस्तर में कांग्रेस अपनी परिवर्तन यात्रा निकाल रही थी। 25 मई 2013 की शाम यह यात्रा सुकमा की ओर से लौट रही थी। काफिला जब दरभा क्षेत्र की झीरम घाटी से गुजर रहा था,तभी माओवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। हमले की शुरुआत आईईडी विस्फोट से हुई। इसके बाद सड़क पर पेड़ गिराकर रास्ता बंद किया गया और जंगल से काफिले पर गोलियां बरसाई गईं। कुछ ही देर में पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। नक्सलियों ने नेताओं और सुरक्षाकर्मियों को अलग-अलग कर दिया। माओवादियों का खास निशाना महेंद्र कर्मा थे। नंदकुमार पटेल,उनके बेटे दिनेश पटेल और कई अन्य लोगों की भी हत्या कर दी गई। एक ही हमले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश नेतृत्व के कई प्रमुख नेताओं की मौत हो गई थी। झीरम हमला अचानक लिया गया फैसला नहीं था। इसके लिए कई सप्ताह पहले से तैयारी चल रही थी।

मिनपा से दरभा कैसे बदला टारगेट

माओवादियों की शुरुआती योजना सुकमा के मिनपा क्षेत्र में सुरक्षा बलों की चौकी पर हमला करने की थी। फरवरी 2013 में बीजापुर के पिडिया गांव में हुई बैठक में रणनीति बदली गई। बैठक में फैसला हुआ कि हमला मिनपा के बजाय दरभा क्षेत्र में किया जाएगा। यह निर्णय वरिष्ठ माओवादी कमांडर देवजी की मौजूदगी में लिया गया था।

मुख्यमंत्री साय ने कहा...न्याय की हुई जीत

झीरम घाटी नक्सली हमले के मामले में जगदलपुर की विशेष एनआईए अदालत द्वारा 10 दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने झीरम घाटी हत्याकांड को छत्तीसगढ़ के इतिहास का पीड़ादायक अध्याय बताते हुए हमले में जान गंवाने वाले नेताओं,सुरक्षाकर्मियों और आम नागरिकों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री साय ने अपने पोस्ट में लिखा कि झीरम घाटी में हुआ बर्बर हत्याकांड छत्तीसगढ़ के इतिहास का ऐसा पीड़ादायक अध्याय है,जिसकी कटु स्मृतियां लंबे समय तक पीड़ा देती रहेंगी। उन्होंने कहा कि इस जघन्य कम्युनिस्ट हिंसा में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं,सुरक्षाकर्मियों और आम नागरिकों को खोना पड़ा। सीएम ने कहा कि मामले में दोषी पाए गए 10 माओवादियों को जगदलपुर एनआईए कोर्ट द्वारा दी गई मृत्युदंड की सजा न्याय की जीत है। उन्होंने एनआईए की जांच की भी सराहना करते हुए कहा कि एजेंसी ने जिस तरह इस जांच को अंजाम तक पहुंचाया,उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उनके दृढ़ नेतृत्व और संकल्प के चलते प्रदेश को सशस्त्र माओवाद के चंगुल से मुक्त कराया गया है। सीएम के मुताबिक,दशकों तक माओवादी हिंसा झेलने वाला बस्तर अब शांति, विश्वास और विकास के नए दौर की ओर बढ़ रहा है। सीएम साय ने अपने पोस्ट में माओवाद को वैचारिक या बौद्धिक समर्थन देने वालों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह अवसर उन लोगों के लिए आत्मचिंतन का है,जो जनजातीय समाज की पीड़ा पर राजनीति करते हैं और आतंक को बौद्धिक एवं वैचारिक समर्थन देते हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि निहित स्वार्थों के कारण किसी भी प्रकार के आतंक को प्रश्रय या आसरा देने का परिणाम विनाशकारी होता है। लोकतंत्र और संविधान के विरुद्ध हिंसा करने वाले आतंक को किसी विचार या क्षेत्र की सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। अंत में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने झीरम घाटी हमले में जान गंवाने वाले सभी लोगों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की।

एनआईए की जांच बिल्कुल ठीक थी : गृहमंत्री विजय शर्मा

विजय शर्मा ने कहा...'एनआईए की जांच बिल्कुल ठीक थी, तभी तो ऐसा हुआ है। अनावश्यक किसी को आरोपित करना और इस विषय पर राजनीतिक करना,कांग्रेस ने कोशिश की थी। लेकिन एनआईए कोर्ट ने आज दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उन्होंने कहा...कि आज यह स्पष्ट हो गया है कि एनआईए ने पूरे शिद्दत के साथ मामले की जांच की थी।

इस जनसंहार को जिन्होंने अंजाम दिया,वे बाहर घूम रहे : भूपेश बघेल

भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा,झीरम राजनीतिक जनसंहार के मामले में नक्सलियों के पैदल पियादों को दी गई सजा न अनुपातिक है और न इसे न्याय कहा जा सकता है। जिन्होंने षड्यंत्र रचा और जिन्होंने इस जनसंहार को अंजाम दिया,वे तो अभी भी बाहर खुले घूम रहे हैं। नक्सलियों के बड़े नेताओं का नाम,पता नहीं किसके इशारे पर,एनआईए ने पहले ही हटा दिए थे। उन पर तो आरोप भी नहीं लगाया गया। न एनआईए ने षड्यंत्र की जांच की,न जांच आयोग ने इसकी जांच की। भाजपा के नेता लगातार अड़ंगा अटकाते रहे और जांच नहीं होने दी। अदालत के फैसले से हमारी सोच बदलने का प्रश्न ही नहीं है। हम अब भी मानते हैं कि न्याय अधूरा है,क्योंकि जांच अधूरी है।

बड़े नक्सलियों को कब मिलेगी सजा : दीपक बैज

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा... कि 10 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है,लेकिन ये 10 लोग कौन हैं? उन्होंने ने दावा किया कि ये वो छोटे नक्सली हैं,जो बड़े नक्सलियों का झोला उठाते थे,राशन इकट्ठा करते थे और पानी पिलाने का काम करते थे,इन्हें सजा दी गई है। बड़े नक्सली सरकार की गोद और उनके संरक्षण में है,उन्हें सजा कब मिलेगी? फैसला आया है,लेकिन न्याय नहीं मिला, असली न्याय तब मिलेगा,जब सरकार के षड्यंत्रकारियों को फांसी की सजा होगी। बैज ने कहा कि सरकार बड़े नक्सलियों को बचाने का काम कर रही है, ताकि उनके षड्यंत्र का पर्दाफाश न हो सके,गांवों के छोटे नक्सलियों को सजा देने का काम किया गया है। इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने की क्षमता इन छोटे नक्सलियों में नहीं थी, जिन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए,उन्हें सजा हुई है, जबकि बड़े नक्सली सरकार के संरक्षण में हैं।

छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग में 165 अधिकारी-कर्मचारियों के तबादले

रायपुर,16 सितम्बर 2026। छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। विभाग ने जिला आबकारी अधिकारी,सहायक जिला आबकारी अधिकारी,आबकारी उपनिरीक्षक, हेड कॉन्स्टेबल,कॉन्स्टेबल,क्लर्क,ड्राइवर,प्यून समेत 165 अधिकारी-कर्मचारियों की पदस्थापना बदली है। जारी सूची के मुताबिक रायपुर, कोरबा, सरगुजा, बिलासपुर,जशपुर,बस्तर,कांकेर,दुर्ग, राजनांदगांव, नारायणपुर समेत कई जिलों में पदस्थ कर्मचारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। कुछ तबादले प्रशासनिक आधार पर, जबकि कई कर्मचारियों के स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर किए गए हैं।

12 डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर्स का ट्रांसफर : नई जारी ट्रांसफर लिस्ट में 12 डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर्स को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। इसके अलावा,31 असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर्स और 57 एक्साइज सब-इंस्पेक्टर्स के काम करने की जगहें भी बदली गई हैं। डिपार्टमेंट में यह एडमिनिस्ट्रेटिव फेरबदल सिर्फ़ ऑफिसर्स तक ही सीमित नहीं है। फील्ड स्टाफ, ऑफिस और सपोर्ट स्टाफ को भी रीअसाइन किया गया है।

कॉन्स्टेबल से ड्राइवर और चपरासी तक ट्रांसफर : ऑर्डर के मुताबुक, 39 हेड कॉन्स्टेबल और कॉन्स्टेबल का भी ट्रांसफर किया गया है। 12 क्लर्क और 14 ड्राइवर और चपरासी को नई पोस्टिंग दी गई है। इससे एक्साइज डिपार्टमेंट की नई जारी लिस्ट में ट्रांसफर की कुल संख्या 165 ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज हो गई है।

रायपुर के गुढ़ियारी थाने में कांग्रेस का प्रदर्शन

भाजयुमो नेताओं की गिरफ्तारी की मांग,टीआई के चेंबर में तोड़फोड़ का आरोप

रायपुर,16 सितम्बर 2026। गुढ़ियारी थाने में हुई तोड़फोड़ और पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में शहर कांग्रेस ने बुधवार को प्रदर्शन किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता गुढ़ियारी थाने के सामने पहुंचे और धरना देकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने घटना के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर गृह मंत्री विजय शर्मा और स्थानीय भाजपा विधायकों के खिलाफ भी नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह घटना पूरे छत्तीसगढ़ और राजधानी रायपुर में अपने आप में पहली घटना है,जब गृह मंत्री के शहर में रहते हुए उनके विभाग के पुलिस अधिकारी और राजधानी के टीआई नरेंद्र साहू के साथ थाने में दुर्व्यवहार,धक्का-मुक्की और उनके नामपट्टिका सहित कार्यालय में तोड़फोड़ की घटना हुई। घटना के करीब 24 घंटे बाद भी किसी दोषी की गिरफ्तारी नहीं होने पर शहर कांग्रेस ने आक्रोश जताया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि घटना के बाद डीजे गाड़ी और आरोपियों की गाड़ियां राजनीतिक दबाव में छोड़ दी गईं। उन्होंने इसे पुलिस पर भाजपा नेताओं के कथित दबाव का प्रमाण बताया। इसी मुद्दे को लेकर शहर कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में गुढ़ियारी थाने के सामने पहुंचे और टीआई से मिलने का प्रयास किया। कांग्रेसजन अपने साथ फूलों का गुलदस्ता लेकर आए थे, जिसे वे टीआई नरेंद्र साहू को देकर उनका तथा पुलिस कर्मचारियों का नैतिक समर्थन करना चाहते थे। शहर कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। 4-5 थानों के टीआई,एएसपी पूर्णिमा लांबा समेत कई अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को थाने के बाहर रोक दिया। इस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नाराजगी जताई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि पुलिस ने कल थाने में तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ भी इसी तरह कार्रवाई की होती तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। टीआई नरेंद्र साहू को गुलदस्ता नहीं देने देने के पुलिस अधिकारियों के रवैये से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता थाने के मुख्य द्वार के सामने धरने पर बैठ गए और करीब दो घंटे तक नारेबाजी करते रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री विजय शर्मा और भाजपा के स्थानीय विधायकों के खिलाफ पोस्टर लहराए। उन्होंने उनके संरक्षण में रायपुर को 'अपराधपुर' और 'गुंडापुर' बनाने का आरोप लगाया तथा पुलिस के साथ कथित दुर्व्यवहार और मारपीट की घटना को पुलिस का मनोबल तोड़ने वाली घटना बताया। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री रायपुर सहित पूरे प्रदेश में अपराध नियंत्रण करने में 32 महीने में विफल साबित हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अब उनके अपने विभाग के टीआई स्तर के अधिकारियों और उनके कार्यालय को भी भाजपा के कार्यकर्ताओं से नहीं बचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 32 महीने में गृह मंत्री ने शहर में बढ़ते अपराधों को नियंत्रित करने के लिए एक बार भी समीक्षा बैठक नहीं की और वे सिर्फ रील बनाने में व्यस्त हैं। टीआई को गुलदस्ता देने के प्रयास को लेकर उन्होंने कहा कि पुलिस जब गलत करेगी तो कांग्रेस सड़क पर आकर उसका विरोध करेगी और जब पुलिस कानून का पालन करने का प्रयास करेगी तो उसके सम्मान के लिए कांग्रेसजन सड़क पर आकर आवाज उठाएंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग पुलिस के टीआई से धक्का-मुक्की और दुर्व्यवहार कर सकते हैं, वे आम लोगों के साथ क्या कर सकते हैं।

कांग्रेस ने पूछा...आरोपी थाने से बाहर कैसे गए?

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि जब थाना परिसर में पुलिस अधिकारियों के सामने तोड़फोड़ की गई, तो एफआईआर के बाद आरोपी थाने से बाहर कैसे चले गए? कांग्रेस ने मामले में सभी आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी करने की मांग की।

कांकेर में 17 साल की लड़की से गैंगरेप : घूमने के बहाने जंगल ले गया,3 दोस्तों के साथ मिलकर वारदात,चारों आरोपी अरेस्ट

कांकेर,16 सितम्बर 2026। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 17 साल की नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि लड़की अपने एक परिचित युवक के साथ घूमने गई थी। लेकिन आरोपी उसे जंगल की ओर ले गया और अपने साथियों को बुला लिया। आरोपी ने अपने 3 साथियो के साथ मिलकर नाबालिग से रेप किया। पीड़िता के घर नहीं लौटने पर पिता ने थाने में शिकायत की। नाबालिग घर से करीब 30 किलोमीटर दूर जंगल में मिली। इस मामले में पुलिस ने बुधवार को 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है। मामला कांकेर कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, नाबालिग मंगलवार रात करीब 9 बजे अपने एक परिचित के साथ घर से निकली थी। देर रात तक वापस नहीं आने पर परिजनों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। कोतवाली पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच शुरू की और नाबालिग की तलाश शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस को नाबालिग कांकेर से करीब 30 किलोमीटर दूर कोरर क्षेत्र के जंगल में मिली। शुरुआती पूछताछ में नाबालिग ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया।

मुख्यमंत्री साय ने एचडीएफसी बैंक के छत्तीसगढ़ में 25 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष लोगो का किया विमोचन

युवाओं,महिलाओं,किसानों और छोटे उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका : मुख्यमंत्री साय

रायपुर,16 सितम्बर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में एचडीएफसी बैंक के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को एचडीएफसी बैंक द्वारा छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाओं के 25 वर्ष पूर्ण किए जाने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री साय ने इस उपलब्धि पर बैंक प्रबंधन,अधिकारियों-कर्मचारियों और ग्राहकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर उन्होंने बैंक के छत्तीसगढ़ में 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में तैयार किए गए विशेष लोगो का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री साय ने बैंक के प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कहा कि किसी भी प्रदेश की आर्थिक प्रगति में मजबूत और सर्वसुलभ बैंकिंग व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पिछले वर्षों में बैंकिंग सेवाओं में तेजी से विस्तार हुआ है और डिजिटल तकनीक ने वित्तीय सेवाओं को पहले से अधिक सहज बनाया है। अब आवश्यकता इस बात की है कि आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं का लाभ केवल बड़े शहरों और व्यावसायिक केंद्रों तक सीमित न रहे, बल्कि गांवों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों तक भी समान रूप से पहुंचे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बैंकिंग नेटवर्क का और विस्तार करते हुए विशेष रूप से बस्तर एवं सरगुजा अंचल के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच बढ़ानी चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण और जनजातीय बहुल है। इन क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता बढ़ने से लोगों को आर्थिक गतिविधियों से जुड़ने के अधिक अवसर मिलेंगे और सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी अधिक सुगमता से उन तक पहुंच सकेगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि गांव के नजदीक बैंक की शाखा या बैंकिंग सुविधा उपलब्ध होने का प्रभाव केवल बैंकिंग लेन-देन तक सीमित नहीं रहता। इसके दूरगामी सामाजिक और आर्थिक परिणाम होते हैं। ग्रामीणों को अपने खाते से संबंधित सामान्य कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ता, उनका समय और संसाधन बचता है तथा बचत और औपचारिक बैंकिंग के प्रति उनका विश्वास बढ़ता है। ऋण, बीमा, डिजिटल भुगतान और अन्य वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच मिलने से परिवारों के आर्थिक सशक्तीकरण का मार्ग भी प्रशस्त होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज केंद्र और राज्य सरकार की अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं की राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में पहुंच रही है। ऐसे में अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग सेवाओं की सहज उपलब्धता सुशासन की व्यवस्था को भी मजबूत करती है। बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार का लाभ नागरिकों के साथ-साथ शासन को भी मिलता है,क्योंकि इससे योजनाओं का लाभ पारदर्शी, सुरक्षित और समयबद्ध ढंग से हितग्राहियों तक पहुंचाने में सहायता मिलती है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार से स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी नई ऊर्जा आती है। किसानों को कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता, युवाओं को स्वरोजगार और उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण तथा छोटे व्यवसायियों को अपने कारोबार के विस्तार के लिए पूंजी आसानी से उपलब्ध हो सकती है। इससे गांवों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी तैयार होते हैं। मुख्यमंत्री साय ने महिला स्व-सहायता समूहों की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं आज स्व-सहायता समूहों के माध्यम से विभिन्न आजीविका गतिविधियों और छोटे उद्यमों से जुड़कर आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं।

CGPSC केस...एडिशनल कलेक्टर चेतन बोरघरिया की बढ़ी रिमांड

8 दिन फिर रायपुर सेंट्रल जेल में बंद रहेंगे,ईडी ने 11 सितंबर को किया था गिरफ्तार

रायपुर,16 सितम्बर 2026। CGPSC राज्य सेवा परीक्षा 2021 में गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार बलरामपुर-रामानुजगंज के एडिशनल कलेक्टर चेतन बोरघरिया को बुधवार को ईडी कोर्ट में पेश किया गया। जहां से कोर्ट ने फिर 8 दिनों के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। वो रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद रहेंगे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के OSD रहे चेतन बोरघरिया को ईडी ने 11 सितंबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा था। पूछताछ पूरी होने के बाद आज की ओर से बोरघरिया कोर्ट में पेश किया गया था। एजेंसी पूछताछ के दौरान सामने आई जानकारी और दस्तावेजों के आधार पर आगे की जांच कर रही है।

3 करोड़ से ज्यादा की अवैध रकम लेने का आरोप : ईडी की जांच के मुताबिक, उत्कर्ष चंद्राकर, अनिल चंद्राकर और डॉ. विकास चंद्राकर ने CGPSC राज्य सेवा परीक्षा 2021 के अलग-अलग अभ्यर्थियों से 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की कथित अवैध रकम जुटाई। आरोप है कि अभ्यर्थियों को पहले ही प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने और उनका चयन कराने का भरोसा दिया गया था। इसके लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री कार्यालय में अपने कथित संपर्क और प्रभाव का इस्तेमाल करने की बात कही गई। जांच में यह भी सामने आया कि ऐसे आश्वासनों के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री कार्यालय में OSD रहे चेतन बोरघरिया के नाम और उनके आधिकारिक पद का कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया।

मोबाइल की फोरेंसिक जांच में बातचीत सामने आई : ईडी के मुताबिक, जब्त डिजिटल डिवाइस की फोरेंसिक जांच में चेतन बोरघरिया और उत्कर्ष चंद्राकर के बीच हुई बातचीत सामने आई। इनमें वित्तीय लेन-देन और रकम वापस करने या भुगतान की मांग से संबंधित बातचीत भी शामिल थी। जांच में M/s Figurecave E-Com (OPC) Private Limited से जुड़े कई वित्तीय लेन-देन भी सामने आए हैं। ईडी को संदेह है कि इस कंपनी का इस्तेमाल रकम को अलग-अलग स्तर पर घुमाने और फंड की लेयरिंग के लिए किया गया।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)